राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

क्रांति समय

कार्यालय ऑफिस

क्रांति समय
दैनिक समाचार में
प्रेसनोट, नोटिस, वेपार संबंधित संपर्क करें
संपर्क नं.-7490923915
ईमेल:-info.krantisamay@gmail.com

सुरत गुजरात से प्रकाशित, मुंबई, उत्तरप्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्यप्रदेश, उत्तरांचल, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा में प्रकाशित

सुरत-गुजरात, संस्करण रविवार 20 सितंबर 2026 वर्ष-9,अंक-229 पृष्ठ-08 मूल्य-01 रूपये

Website : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

पहला कॉलम

पीएम मोदी-भारत जी-20 का इकलौता देश, जलवायु प्रतिबद्धताओं को समय से पहले पूरा किया

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का मोबाइल एप लांच किया

नई दिल्ली ।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया, जहाँ उन्होंने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) का मोबाइल एप लांच किया। इस मौके पर, प्रधानमंत्री मोदी ने महत्वपूर्ण घोषणा कर कहा कि भारत जी-20 देशों में एकमात्र ऐसा राष्ट्र है जिसने पेरिस में हुए कोप-21 शिखर सम्मेलन में किए अपने सभी जलवायु प्रतिबद्धताओं को समय से पहले पूरा किया है।

प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि कार्बन उत्सर्जन की जिम्मेदारी अक्सर गलत तरीके से विकासशील देशों पर डाली जाती है, जबकि ऐतिहासिक सच्चाई यह है कि भारत का प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन आज भी वैश्विक औसत के आधे से भी कम है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ के कई देश इस चुनौती का सामना कर रहे हैं।गौरतलब है कि पेरिस में 2015 में हुए कोप-21 सम्मेलन में भारत ने पर्यावरण को लेकर तीन प्रमुख लक्ष्य निर्धारित किए थे।

इसमें पहला लक्ष्य 2030 तक 2005 के मुकाबले कार्बन उत्सर्जन की तीव्रता को 33-35 प्रतिशत कम करना था। दूसरा, देश की बिजली क्षमता का लगभग 40 प्रतिशत हिस्सा गैर-जीवाश्म ऊर्जा स्रोतों से तैयार करना था, और तीसरा लक्ष्य पेड़ और जंगल बढ़ाकर 2.5-3 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड सोखने की क्षमता तैयार करना था। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा पर विशेष ध्यान केंद्रित करके इन लक्ष्यों को निर्धारित समय से पहले ही हासिल किया है, जो नए भारत की ताकत को दिखाता है।

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा 19 और 20 सितंबर को आयोजित दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस पर्यावरण और जलवायु से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर केंद्रित है। इसमें न्यायिक, सरकारी और कानूनी क्षेत्रों से जुड़े विशेषज्ञ और प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। उद्घाटन सत्र में भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव, अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी और एनजीटी के चेयरपर्सन जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव जैसे गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

देश की अलग-अलग हाईकोर्ट में 14 जजों की नियुक्ति, दिल्ली हाईकोर्ट को मिले 7 जज

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने दिल्ली हाईकोर्ट के जजों के लिए 8 की सिफारिश भेजी थी

नई दिल्ली।

केंद्र सरकार ने शनिवार को अलग-अलग हाईकोर्ट में 14 जजों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी। केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने शनिवार को एक्स पर जजों की सूची जारी करते हुए लिखा- भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद, राष्ट्रपति न्यायिक अधिकारियों को उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश/अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करते हैं दिल्ली हाईकोर्ट में कुल 7 जजों की नियुक्ति की गई है। निवेदिता अनिल शर्मा और निशा सहाय सक्सेना को स्थायी जज नियुक्त किया है। वहीं, संजय शर्मा, भरत पाराशर, अदिति चौधरी, दिनेश भट्ट और अरुण भारद्वाज को अतिरिक्त जज नियुक्त किया है। अरुण भारद्वाज अभी दिल्ली हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इससे पहले 10 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने दिल्ली हाईकोर्ट के जजों के लिए 8 न्यायिक अधिकारियों की सिफारिश भेजी थी। हालांकि, केंद्र सरकार ने उनमें से सिर्फ 7 नामों को मंजूरी दी है। दिल्ली हाईकोर्ट में जजों की कुल स्वीकृत संख्या 60 है। फिलहाल वहां 44 जज काम कर रहे हैं यानी 16 पद खाली हैं। झारखंड हाईकोर्ट में तीन नए जज नियुक्त किए गए हैं, जिनमें मनोज प्रसाद, अखिल कुमार और राम शर्मा शामिल हैं। झारखंड हाईकोर्ट में जजों की स्वीकृत संख्या 25 है। अभी तक यहां 13 जज काम कर रहे थे और 12 पद खाली थे। नई नियुक्तियों के बाद हाईकोर्ट में काम करने वाले जजों की संख्या बढ़कर 16 हो जाएगी। सरकार ने शनिवार को यश पॉल बोर्नी की जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के जज के तौर पर नियुक्ति की घोषणा की। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 10 सितंबर को हुई बैठक में हाईकोर्ट जज के तौर पर उनकी नियुक्ति के लिए उनके नाम की सिफारिश की थी। इसके अलावा केंद्र सरकार ने कर्नाटक हाईकोर्ट में तीन न्यायिक अधिकारियों को अतिरिक्त जज के तौर पर नियुक्त करने की मंजूरी दी, जिन तीन न्यायिक अधिकारियों को प्रमोट किया है, उनमें उषा रानी, केएस भरत कुमार और नेराले वीरभद्रैया भवानी शामिल हैं। कर्नाटक हाईकोर्ट में अभी 62 जजों की मंजूर संख्या के मुकाबले 54 जज हैं। इन तीन नए जजों के पद संभालने के बाद इन जजों की संख्या बढ़कर 57 हो जाएगी।

टीएमसी सिंबल फीज पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचीं ममता..ईसी के फैसले को बताया गलत

बागी गुट ने चुनाव आयोग के फैसले का स्वागत किया

नई दिल्ली।

पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जहाँ उन्होंने चुनाव आयोग (ईसी) के उस फैसले को चुनौती दी है, जिस फैसले में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) का नाम और उसका प्रतिष्ठित फूल और घास (जोड़ा घास फूल) वाला पारंपरिक चुनाव चिह्न फ्रीज किया गया है। यह महत्वपूर्ण कदम 6 अक्टूबर को होने वाले नंदीग्राम उपचुनाव से ठीक पहले आया है, इस फैसले ने राज्य की राजनीतिक लड़ाई को और तेज किया है। यह विवाद टीएमसी के भीतर ममता और रिताब्रता बनर्जी के गुटों के बीच पारंपरिक फूल और घास चुनाव चिह्न पर दावेदारी को लेकर चल रहे आपसी झगड़े का नतीजा है। चुनाव आयोग ने दोनों गुटों को इस चिह्न के इस्तेमाल से रोका है। चुनाव आयोग के फैसले के अनुसार, ममता के गुट को अब ममता ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस नाम और फुटबॉल खिलाड़ी का चुनाव चिह्न दिया है, जबकि विरोधी गुट को डेमोक्रेटिक तृणमूल कांग्रेस नाम के साथ लिफाफा चुनाव चिह्न आवंटित किया है। कोलकाता में पूर्व मुख्यमंत्री ममता ने चुनाव आयोग के फैसले को भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास का काला दिन बताया।

टहलने गए लोगों ने पेड़ से लटका देखा युवक का शव, हत्या की आशंका

महराजगंज।

खेत के किनारे पेड़ से युवक का शव लटका मिला। युवक के दोनों पैर जमीन पर टिके हुए थे। वहीं, घटनास्थल से कुछ दूरी पर उसकी बाइक बरामद हुई है। इसको लेकर हत्या के बाद शव लटकाए जाने की आशंका जताई जा रही है। मीडिया रिपोर्ट के मताबिक निचलौल थाना क्षेत्र के बरगदही गांव के पास शनिवार सुबह खेत की ओर टहलने गए लोगों की नजर पेड़ से लटके शव पर पड़ी। कुछ ही देर में बड़ी संख्या में ग्रामीण वहां जुट गए। सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को नीचे उतरवाकर आसपास के क्षेत्र की जांच-पड़ताल की। मृतक की पहचान अरुण राजभर (28) निवासी कोहड़वल टोला सिसवा डीह के रूप में हुई। घटना की जानकारी मिलते ही मृतक के परिजन मौके पर पहुंचे। थाना प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि पुलिस टीम मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है।

ममता के दखल के बाद चौधरी का यू-टर्न- वापस लिया चुनाव से हटने का फैसला

रेजीनगर उपचुनाव प्रत्याशी ने कुछ घंटे पहले ही प्रशासन पर कार्यकर्ताओं को परेशान करने का लगा, चुनाव से हटने का किया था ऐलान

कोलकाता।

पश्चिम बंगाल के रेजीनगर विधानसभा उपचुनाव में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के उम्मीदवार रबीउल आलम चौधरी ने चुनाव से हटने की घोषणा के कुछ घंटे बाद ही अपना फैसला बदल दिया। शनिवार को चौधरी ने कहा कि वह उपचुनाव लड़ना जारी रखेंगे। उन्होंने बताया कि उन्होंने पार्टी प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कहने पर अपना फैसला वापस लिया है।

चौधरी ने इससे पहले नए चुनाव चिन्हे के साथ चुनाव लड़ने में परेशानी होने के साथ ही राज्य प्रशासन पर पार्टी कार्यकर्ताओं को परेशान करने का आरोप लगाया और चुनाव से हटने की घोषणा की थी। उनका कहना था कि कार्यकर्ताओं को प्रचार करने से रोका जा रहा है और कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके बाद उनके चुनाव से हटने की खबर सामने आई थी। बाद में चौधरी ने कहा कि ममता बनर्जी के निर्देश के बाद उन्होंने अपना निर्णय बदल दिया है। उन्होंने कहा कि वह पार्टी नेतृत्व के निर्देशों से अलग जाकर कोई कदम नहीं उठा रहे हैं। चौधरी के मुताबिक, पहले उन्होंने नए चुनाव चिह्न और अन्य चुनावी मुद्दों पर निर्णय लेने की बात सोची थी। अब वह नए चुनाव चिह्न के साथ मतदाताओं के बीच जाएंगे।

गौरतलब है कि 13 सितंबर को पार्टी ने रेजीनगर से रबीउल आलम चौधरी और नंदीग्राम से संचिता प्रधान (डे) को उम्मीदवार घोषित किया था। पार्टी ने दोनों नामों की घोषणा ममता बनर्जी के मार्गदर्शन और प्रेरणा से किए जाने की बात कही थी। चौधरी के फैसले में यह बदलाव नंदीग्राम से पार्टी की उम्मीदवार संचिता प्रधान डे द्वारा नामांकन वापस लेने के एक दिन बाद हुआ है। प्रधान ने शुक्रवार को अपना नामांकन वापस ले लिया था।

होमगार्ड ने महिला को बाल पकड़कर घसीटा, निलंबन के साथ हुआ गिरफ्तार

हैदराबाद।

हैदराबाद के हाफिजपेट रेलवे स्टेशन पर चौंकाने वाली घटना सामने आई, जहाँ एक होमगार्ड जवान ने एक महिला को बेरहमी से पीटा और उसके बाल पकड़कर जमीन पर घसीटा। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर आरोपी होमगार्ड जवान को गिरफ्तार किया है और ड्यूटी से हटा दिया है।

पुलिस ने बताया कि शुरुआती जांच में पता चला है कि होमगार्ड की ड्यूटी रेलवे स्टेशन पर लगी थी और पीड़ित महिला कचरा बीनने का काम करती है। पुलिस के मुताबिक, दोनों के बीच किसी बात को लेकर बहस हुई थी, जिसके दौरान महिला ने कथित तौर पर होमगार्ड को गाली दी थी, जिसके बाद यह हिंसक झड़प हुई। आरोपी होमगार्ड के खिलाफ थाने में संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है और न्यायिक हिरासत में भेजने के लिए कोर्ट में पेश किया जा रहा है। साउथ सेंट्रल रेलवे ने घटना की पुष्टि कर बताया कि आरोपी तेलंगाना स्टेट पुलिस का होमगार्ड था और आगे की विभागीय कार्रवाई के लिए संबंधित पुलिस विभाग को सौंप दिया गया है। पुलिस प्रशासन ने जोर देकर कहा है कि वे ऐसी घटनाओं को बेहद गंभीरता से लेते हैं ।

बरसाना-जहां आज भी अमर है राधा-कृष्ण का सच्चा प्रेम

नई दिल्ली।

प्रेम और भक्ति के अनूठे संगम बरसाना में आज भी राधा-कृष्ण का अमर प्रेम जीवंत है। वृषभानु नंदनी राधारानी का जन्मोत्सव यहां बड़े उत्साह और उमंग के साथ मनाया जा रहा है, जिसने पूरे क्षेत्र को भक्ति के रंगों से सराबोर किया है। राधारानी के निज महल को भव्य तरीके से सजाया गया है और उत्सव में शामिल होने के लिए देश-विदेश से श्रद्धालुओं का बरसाना पहुंचे है। यह स्थान सिर्फ एक तीर्थ नहीं, बल्कि राधा रानी और भगवान श्रीकृष्ण के दिव्य प्रेम की अनूठी कहानियों को सजीव रखने वाला एक पवित्र धाम है, जहां जिंदगी में एक बार हर किसी को जरूर जाना चाहिए।

बरसाना की यात्रा इन्हीं प्रेम गाथाओं में डूबने का मौका देती है। यहां के मंदिरों और स्थलों में सबसे प्रमुख है श्री राधा रानी मंदिर, जिस करोड़ों भक्त लाडली जी का मंदिर भी कहते हैं। ब्रह्मांचल पर्वत की ऊंचाइयों पर स्थित यह मंदिर राधा रानी के दुलारे और प्रिय रूप की आराधना का केंद्र है। इसकी प्राचीन वास्तुकला और धार्मिक आस्था का अद्भुत मिश्रण विशेष बनाता है। राधाष्टमी और होली जैसे महापर्वों पर यहां हजारों भक्तों का तांता लगा रहता है। निकट ही स्थित माणगढ़ पहाड़ी पर माणगढ़ मंदिर बना है, जो राधारानी की बाल्यकाल की लीलाओं और उनके सखाओं के साथ बिताए गए क्षणों को दिखाता है। यहां की शांत और प्राकृतिक सुंदरता भक्तों को गहरे आध्यात्मिक अनुभव से भर देती है।

इसके अलावा, बरसाना के पास ही कृष्ण कुंड है, जिसके बारे में मान्यता है कि यह राधा और कृष्ण की जल क्रीड़ाओं का साक्षी रहा है।

आगर मालवा में भीषण हादसा-उफनते नाले में बही कार, 8 श्रद्धालुओं की मौत

आगर मालवा।

मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले में भयावह सड़क हादसा सामने आया है, जहां श्रद्धालुओं से भरी कार बारिश से उफनते नाले में बह गई। इस दर्दनाक घटना में तीन बच्चों सहित कुल आठ लोगों की जान चली गई। यह हादसा नलखेड़ा स्थित प्रसिद्ध मां बगलामुखी मंदिर के समीप हुआ। मिली जानकारी के अनुसार, मृतक श्रद्धालु मां बगलामुखी के दर्शन करने नलखेड़ा पहुंचे थे। शुक्रवार देर रात या शनिवार सुबह, जब कार चालक ने मंदिर के समीप बरसाती नाले को पार करने का प्रयास किया, तब वहां पानी के तेज बहाव का सही अंदाजा नहीं लग सका। नतीजतन, कार अनियंत्रित होकर नाले के भीषण बहाव में बह गई। शनिवार की सुबह जब नाले का पानी कुछ उतरा, तब राहगीरों की नजर बही हुई कार पर पड़ी। उन्होंने तत्काल पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद राहत और बचाव कार्य शुरू किया। कार के भीतर से सभी आठ शवों को बाहर निकाला गया।आगर मालवा पुलिस ने घटना में आठ मौतों की पुष्टि की है। मरने वालों में तीन बच्चे, दो महिलाएं और तीन पुरुष शामिल हैं। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि कार में सवार सात लोग ओडिशा के निवासी थे, जिन्होंने उज्जैन से कार किराए पर ली थी और वे मां बगलामुखी के दर्शनों के लिए जा रहे थे। इस हृदयविदारक हादसे के बाद मौके पर भारी संख्या में लोग जुट गए और अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

निलेकणी की अध्यक्षता वाली उच्च समिति की कार्यस्थिति की रिपोर्ट पेश करे केंद्र सरकार

विवाद के बाद नीट-यूजी परीक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त

नई दिल्ली।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह प्रतियोगी परीक्षा की सुरक्षा व विश्वसनीयता को मजबूत करने के लिए इन्फोसिस के सह-संस्थापक नंदन निलेकणी की अध्यक्षता वाली उच्च समिति की कार्यस्थिति की रिपोर्ट पेश करे।

न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक अराधे के पीठ ने कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के संयुक्त सचिव से अब तक हुई प्रगति का ब्योरा देते हुए हलफनामा दाखिल करने को कहा। विभाग के संयुक्त सचिव समिति के समन्वयक भी हैं। उन्हें यह हलफनामा दो हफ्ते में जमा करना है और मामले की अगली सुनवाई तीन हफ्ते बाद होगी।

पीठ ने यह भी संकेत दिया कि वह एनटीए के कामकाज और आधारभूत ढांचे का जायजा लेने के लिए उसके मुख्यालय का दौरा कर सकती है। न्यायमूर्ति नरसिम्हा ने कहा कि हम एक दिन वहां आएंगे, मैं और मेरे साथी जज भी। न्यायालय को बताया गया कि एनटीए को मिंटो रोड के पास एक स्थायी जगह आवंटित की गई है। पीठ ने कहा कि फिजिकल इंस्पेक्शन से यह पता लगाने में मदद मिलेगी कि एजेंसी के पास पर्याप्त मानवश्रम है या नहीं और जो तरीके लागू किए गए हैं, वे ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। कोर्ट ने दूसरे सरकारी विभागों से प्रतिनियुक्ति पर आए कर्मचारियों पर मुख्य रूप से निर्भर रहने के बजाय एनटीए में स्थायी मानवश्रम होने की जरूरत पर भी जोर दिया।

पीठ ने कहा कि वहां स्थायी स्टाफ होना चाहिए। साथ ही, दूसरी काम करने वाली संस्थाओं के साथ आपके संबंध, आप उनके साथ कैसे सहयोग कर रहे हैं, कितने आंकड़े हैंज्क्या हमें सांविधिक आधार की जरूरत है?' केंद्र की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि निलेकणी की अध्यक्षता वाली समिति ने साझेदारों के साथ व्यापक बातचीत की है।

उम्मीद है कि समिति सितंबर के आखिर तक अपनी रिपोर्ट सौंप देगी। हालांकि, पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि इस कवायद का नतीजा संस्थागत सुधारों के रूप में निकलना चाहिए, न कि सिर्फ ऐसी रिपोर्ट के तौर पर जो कागजों तक ही सीमित रह जाए। पीठ ने कहा कि सबसे जरूरी चीज संस्थानीकरण है।

पीठ ने कहा कि समिति का हलफनामा रिकॉर्ड पर आने के बाद वह उसकी सिफारिशों पर आगे की कार्रवाई करेगी। मेहता ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि सरकार इन सिफारिशों को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है।

पीठ ने परीक्षा प्रणाली को फिर से डिजाइन करते समय संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों के सुझावों को शामिल करने के महत्त्व पर भी जोर दिया।

यह कार्यवाही नीट-यूजी से जुड़ी अनियमितताओं और प्रश्नपत्र लीक होने के मामलों से संबंधित कई याचिकाओं के कारण शुरू हुई थी।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

अमेरिका की संसद से निकली 100 प्रतिशत टैरिफ मिसाइल!

(लेखक-एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी)

-मूडीज़ ने बढ़ाया भारत का जीडीपी अनुमान 7 प्रतिशत,लेकिन तेल ने बजाई खतरे की घंटी! -भारत की अर्थव्यवस्था का अग्निपरीक्षा काल? - समग्र व्यापक विश्लेषण

अमेरिकी टैरिफ तलवार, महंगा तेल और भारत की अर्थव्यवस्था - ऊर्जा सुरक्षा की अग्निपरीक्षा!

भारत की ऊर्जा सुरक्षा, रणनीतिक स्वायत्तता, महंगाई नियंत्रण,आर्थिक विकास और वैश्विक कूटनीतिक संतुलन, इन सभी की एक साथ अग्नि परीक्षा?

वैश्विक स्तरपर मध्य -पूर्व में जारी संघर्ष, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें और रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर अमेरिका की संभावित 100 प्रतिशत तक अतिरिक्त टैरिफ की तलवार, इन तीनों घटनाक्रमों ने वैश्विक अर्थव्यवस्था के सामने एक साथ कई नई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं।भारत के लिए यह परिस्थिति इसलिए अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि देश अपनी ऊर्जा जरूरतों के एक बड़े हिस्से के लिए आयातित कच्चे तेल पर निर्भर है। एक ओर अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल महंगा होने से आयात बिल, परिवहन लागत और महंगाई पर दबाव बढ़ सकता है,वहीं दूसरी ओर अमेरिका की संसद से पारित लिंडसे ओ.ग्राहम सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट ऑफ़ 2026 ने रूस से ऊर्जा खरीद जारी रखने वाले देशों के लिए नई अनिश्चितता पैदा कर दी है अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने 16 सितंबर को यह विधेयक 262-159 मतों से पारित किया,जबकि सीनेट इसे अगस्त में 86/11 से पहले ही पारित कर चुकी थी। अब विधेयक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हस्ताक्षर की प्रक्रिया में है।यानी गेंद अप ट्रंप के पहले में चली गई है।मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र यह बताना चाहूंगा कि यहां अमेरिकी व्यवस्था को समझना भी जरूरी है।भारत की संसद में जिस प्रकार लोकसभा और राज्यसभा मिलकर कानून बनाने की प्रक्रिया पूरी करती हैं,उसी प्रकार अमेरिका में हाउस ऑफ़ रिप्रेजेन्टेटिव्स यानें प्रतिनिधि सभा और सेनेट यानें सीनेट कांग्रेस के दो सदन हैं।किसी विधेयक को कानून बनने के लिए दोनों सदनों से पारित होना और फिर राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलना आवश्यक होता है।इसलिए फिलहाल इसे भारत पर 100 प्रतिशत टैरिफ लागू हो चुका मानना सही नहीं होगा।मौजूदा स्थिति यह है कि दोनों सदनों से विधेयक पारित हो चुका है और राष्ट्रपति के पास पहुंच गया है।कानून बनने के बाद भी 100प्रतिशत टैरिफ भारत पर अपने आप नहीं लग जाएगा; राष्ट्रपति को उपलब्ध वैधानिक अधिकारों और संबंधित परिस्थितियों के आधार पर कार्रवाई करनी होगी।रिपोर्टों के अनुसार कानून में रूस से ऊर्जा खरीदने वाले प्रमुख देशों पर सटीक 100 प्रतिशत तक टैरिफ लगाने की शक्ति का प्रावधान है, जबकि कुछ परिस्थितियों में रूस की ऊर्जा परनिर्भरता घटाने की दिशा में कदम उठाने वाले देशों के लिए अपवादों की गुंजाइश भी बताई गई है।विदेश मंत्रालय ने 17 सितंबर 2026 को स्पष्ट किया कि भारत अपनी 140 करोड़ से अधिक आबादी की ऊर्जा सुरक्षा के लिए विविध स्रोतों और बदलती बाजार परिस्थितियों के आधार पर निर्णय लेता रहेगा।मंत्रालय ने यह भी कहा कि इस विषय पर अमेरिका के साथ उच्चस्तरीय चर्चा हुई है और भारत अपने व्यापारिक तथा आर्थिक हितों की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाएगा।

साथियों,भारत के लिए असली चुनौती यहीं से शुरू होती है। रूस से कच्चा तेल खरीदने का आर्थिक तर्क यह रहा है कि उपलब्ध परिस्थितियों में रूसी क्रूड भारतीय रिफाइनरियों के लिए प्रतिस्पर्धी कीमत और आपूर्ति विविधीकरण का महत्वपूर्ण स्रोत बना है। यदि अमेरिकी दबाव के कारण भारतीय कंपनियों को रूसी तेल की खरीद घटानी पड़ती है,तो विकल्प के रूप में इराक, सऊदी अरब,संयुक्त अरब अमीरात,अमेरिका, ब्राजील, नाइजीरिया और अंगोला जैसे स्रोतों से खरीद बढ़ाई जा सकती है।लेकिन किसी एक स्रोत को अचानक बड़े पैमाने पर बदलना केवल राजनीतिक निर्णय नहीं होता;इसमें कीमत,क्रूड की गुणवत्ता, रिफाइनरी की तकनीकी जरूरत,समुद्री मालभाड़ा, बीमा,भुगतान व्यवस्था और उपलब्धता जैसे अनेक आर्थिक पहलू शामिल होते हैं।इसलिए भारत का घोषित रुख,ऊर्जा सुरक्षा के लिए विभिन्न देशों से खरीद का विविधीकरण व्यावहारिक रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है।भारत के विदेश मंत्रालय ने भी 17 सितंबर को स्पष्ट किया कि उसकी प्राथमिकता देश की 140 करोड़ विशाल आबादी की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करना है और वह घटनाक्रम पर नजर रख रहा है।

साथियों क़्या इसे 12-13 सितंबर 2026 को भारत की मेजबानी में हुए ब्रिक्स सम्मेलन और भारत-रूस- चीन की सक्रिय कूटनीतिक निकटता की पृष्ठभूमि में देखा जाना चाहिए? इसे सीधे तौर पर ब्रिक्स सम्मेलन की प्रतिक्रिया कहना अभी प्रमाणित तथ्य नहीं होगा। समय का मेल ज़रूर ध्यान आकर्षित करता है,ब्रिक्स बैठक के तुरंत बाद अमेरिकी विधेयक का अंतिम चरण में पहुंचना और रूस-चीन-भारत के बीच आर्थिक एवं रणनीतिक संवाद का लगातार बढ़ना एक व्यापक भू-राजनीतिक संदर्भ बनाता है। लेकिन किसी कानून के पीछे सम्मेलन को प्रत्यक्ष कारण बताने के लिए ठोस सरकारी या विधायी प्रमाण आवश्यक होंगे। इसलिए इसे फिलहाल रणनीतिक प्रतिस्पर्धा की व्यापक पृष्ठभूमि और समय का संयोग,दोनों संभावनाओं के रूप में देखना अधिक तथ्यपरक होगा। अमेरिका का घोषित उद्देश्य रूस की ऊर्जा आय से मिलने वाले आर्थिक संसाधनों पर दबाव बढ़ाना है, जबकि भारत का घोषित उद्देश्य अपनी ऊर्जा सुरक्षा और राष्ट्रीय आर्थिक हितों की रक्षा करना है।इस पूरे घटनाक्रम का दूसरा बड़ा पहलू कच्चे तेल की कीमत है। यदि मध्य-पूर्व का संघर्ष लंबा चलता है और वैश्विक तेल आपूर्ति पर दबाव बना रहता है, तो महंगा रूसी तेल ही नहीं बल्कि गैर-रूसी तेल भी महंगा हो सकता है। ऐसे में भारत के सामने समस्या केवल यह नहीं होगी कि रूस से कितना तेल खरीदना है, बल्कि यह भी होगी कि यदि रूसी आपूर्ति घटती है तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में उपलब्ध अतिरिक्त तेल कितनी कीमत पर मिलेगा। महंगा कच्चा तेल भारत के आयात बिल को बढ़ाता है, रुपये पर दबाव डाल सकता है और पेट्रोल- डीजल, परिवहन, विमानन, रसायन, प्लास्टिक तथा अनेक औद्योगिक क्षेत्रों की लागत को प्रभावित कर सकता है। यही कारण है कि ऊर्जा सुरक्षा को केवल पेट्रोलियम मंत्रालय का विषय नहीं बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था, महंगाई और आम उपभोक्ता से जुड़ा ठीक था से विषय माना जाता है।

साथियों,फिर भी भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए तस्वीर पूरी तरह नकारात्मक नहीं है।वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि का अनुमान 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 7 प्रतिशत कर दिया है।मूडीज के आकलन में मजबूत घरेलू मांग, निवेश और अर्थव्यवस्था की अब तक दिखाई गई मजबूती महत्वपूर्ण कारक हैं। एजेंसी ने साथ ही यह चेतावनी भी दी है कि लंबे समय तक ऊंची ऊर्जा कीमतें और अल नीनो से जुड़ी खाद्य महंगाई भविष्य में जोखिम बढ़ा सकती है। यानी भारत की अर्थव्यवस्था ने बाहरी झटकों को अब तक काफी हद तक संभाला है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि महंगा तेल लंबे समय तक बिना प्रभाव के सटीकता से गुजर जाएगा।

साथियों, इसी संदर्भ में भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति और नकदी प्रबंधन भी महत्वपूर्ण हो जाता है। 17 सितंबर को 50,000 करोड़ रूपए की सरकारी प्रतिभूतियों की ओपन मार्केट ऑपरेशन बिक्री के जरिए अतिरिक्त बैंकिंग लिक्विडिटी को सोखने की प्रक्रिया बाजार के लिए महत्वपूर्ण संकेत है।सामान्य भाषा में समझें तो जब आरबीआई सरकारी बॉन्ड बेचता है, तो बैंकिंग प्रणाली से रुपये की अतिरिक्त नकदी बाहर जाती है।आरबीआई स्वयं स्पष्ट करता है कि ओएमओ बिक्री का उद्देश्य प्रणालीगत तरलता को कम करना है,जबकिओएमओ खरीद तरलता बढ़ाती है।आम ग्राहक के लिए इसका अर्थ यह नहीं है कि उसके बैंक खाते से पैसा निकाल लिया गया या उसकी जमा राशि पर कोई सीधा खतरा पैदा हो गया। यह बैंकिंग प्रणाली और वित्तीय बाजार के स्तर पर होने वाला संस्थागत ऑपरेशन है। हालांकि इसका अप्रत्यक्ष प्रभाव ब्याज दरों के माध्यम से सामने आ सकता है। यदि बैंकिंग प्रणाली में अतिरिक्त नकदी कम होती है तो बाजार की फंडिंग परिस्थितियां बदल सकती हैं और भविष्य में जमा तथा ऋण दरों पर असर पड़ सकता है। लेकिन किसी मौजूदा ऋण की ईएमआई केवल इस ओएमओ बिक्री के कारण तुरंत बढ़ना जरूरी नहीं है; इसका वास्तविक प्रभाव ऋण के प्रकार, ब्याज दर की संरचना और भविष्य में आरबीआई के व्यापकमौद्रिक रुख पर सटीकता से निर्भर करेगा।

साथियों, इस प्रकार सितंबर 2026 में भारत के सामने एक असाधारण आर्थिक संतुलन की स्थिति है। एक तरफ अमेरिका के साथ व्यापारिक संबंध,दूसरी तरफ रूस से प्रतिस्पर्धी ऊर्जा आपूर्ति, तीसरी तरफ मध्य-पूर्व का भू-राजनीतिक संकट और चौथी तरफ घरेलू आर्थिक विकास को बनाए रखने की आवश्यकता।भारत के लिए समाधान किसी एक देश पर निर्भर रहने में नहीं बल्कि ऊर्जा स्रोतों,व्यापारिक साझेदारों,भुगतान प्रणालियों और रणनीतिक भंडार का लगातार विविधीकरण करने में दिखाई देता है।रूस से खरीद,पश्चिम एशिया केपारंपरिक आपूर्तिकर्ता, अमेरिका और अफ्रीकी तथा लैटिन अमेरिकी स्रोत,सभी को परिस्थितियों के अनुसार संतुलित करना भारत की ऊर्जा रणनीति का हिस्सा बन सकता है।दीर्घकाल में घरेलू उत्पादन, नवीकरणीय ऊर्जा, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी,ऊर्जा दक्षता और रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार का विस्तार आयात जोखिम को कम करने में सटीकता से मदद कर सकता है।

साथियों सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत के सामने फिलहाल कोई तत्काल 100 प्रतिशत अमेरिकी टैरिफ लागू नहीं हुआ है,बल्कि उसके लागू होने की संभावित शक्ति वाला अमेरिकी कानून राष्ट्रपति के स्तर पर लंबित है। इसलिए आने वाले दिनों में ट्रंप प्रशासन का निर्णय, भारत -अमेरिका व्यापार वार्ता, रूस से भारतीय तेल खरीद की दिशा, मध्य-पूर्व में संघर्ष की अवधि और अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमत,ये सभी कारक मिलकर आगे की तस्वीर तय करेंगे।

संपादकीय

दर्द देता इलाज

किसी अस्पताल में उपचाराधीन कोई मरीज जब किसी रोग से लड़ रहा होता है तो वह इस स्थिति में नहीं होता कि उपचार में इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरणों व दवा आदि के तार्किक मूल्यों की पड़ताल कर सके। वह यह पूछने की स्थिति में भी नहीं होता कि किसी दवा, सिरिंज या कैथेटर आदि की कीमत जायज है या नाजायज। वैसे भी अस्पताल संचालकों द्वारा संचालित किए जा रहे मेडिकल स्टोरों में वह कीमत को लेकर अपना पक्ष रखने की हालत में नहीं होता। यह विडंबना ही है कि दवा कंपनियां बिचौलियों व मेडिकल स्टोर के मालिकों को लुभाने के लिए दवा की वास्तविक लागत कीमत व कथित एमआरपी में बड़ा फर्क रखती हैं, जिसके चलते दवा विक्रेता मरीजों के तीमारदारों से मनमानी कीमतें वसूल कर मुनाफा कूटते हैं। जिसकी पुष्टि महाराष्ट्र के फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा अस्पतालों में उपयोग किए जाने वाले सामान की कीमतों की राज्यव्यापी पड़ताल के निष्कर्ष करते हैं। फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन महाराष्ट्र के तेजतर्रार कमिश्नर तुकाराम मुंढे की पहल पर किए गये राज्यव्यापी सर्वेक्षण में पाया गया कि एक अस्पताल द्वारा खरीदे गए एक आईवी एन्फ्यूजन सेट की कीमत मात्र 11 रुपये थी और उस पर एमआरपी 325 दर्ज थी, जो वास्तविक कीमत से हजारों फीसदी अधिक थी। एक सिरिंज जिसकी खरीद कीमत 6.7 रुपये थी, उसकी एमआरपी 57 रुपये थी। जबकि 29 रुपये में खरीदा गया कैथेटर 310 रुपये एमआरपी वाला था। निस्संदेह, सप्लाई चेन में भी कुछ खर्च होते हैं, लेकिन अस्पताल व उनके मेडिकल स्टोर इन दवाइयों पर अंधा मुनाफा कमा रहे हैं। यह दुखद ही है कि जहां पहले ही मरीज रोग से पीड़ित होता है, वहां दवाइयों की कीमतों को लेकर पारदर्शिता का अभाव उसके दर्द को बढ़ाने वाला ही होता है। यह उम्मीद जगाने वाली पहल है कि कमिश्नर मुंढे ने एफडीए की पड़ताल के निष्कर्ष और सिफारिश केंद्र सरकार को भेजी है कि मेडिकल उपकरणों की कीमतों की पड़ताल और मुनाफे की सीमा निर्धारण पर गंभीरता से विचार किया जाए। साथ ही इस बाबत सशक्त निगरानी तंत्र विकसित किया जाए। इस तरह अब यह महत्वपूर्ण मामला राष्ट्रीय नियामक संस्थाओं के पास है, जिसमें एनपीपीए और फॉर्मास्यूटिकल विभाग आदि शामिल हैं। यह सुखद है कि मामला एक ईमानदार अधिकारी की सख्त पहल के बाद उजागर हुआ है। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि मरीजों को उलटे उस्तरे से मूंडने का यह खेल दशकों से बदस्तूर जारी है। जिन सरकारों व संबंधित विभागों के अधिकारियों की जिम्मेदारी इसकी निगरानी की थी, वे निहित स्वार्थों के चलते मूकदर्शक बने रहे हैं। महाराष्ट्र में एफडीए के कमिश्नर का पदभार संभालने के बाद मुंढे ने पूरे राज्य में खाद्य पदार्थों में मिलावट व सेहत के लिए हानिकारक खाद्य पदार्थों के खिलाफ एक जोरदार अभियान चला रखा है। इतना ही नहीं, इस सार्थक पहल के बाद एफडीए ने बड़ी मात्रा में लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने वाली असुरक्षित खाद्य सामग्री भी जब्त की है। साथ ही खाद्य सुरक्षा के नियमों का उल्लंघन करने वाले कई नामी प्रतिष्ठानों व तथाकथित दिग्गजों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। विडंबना यह है कि खाद्य पदार्थों और चिकित्सा उपयोग में आने वाली वस्तुओं की कीमत व गुणवत्ता की जांच-पड़ताल और इनसे खुद को सुरक्षित रखने की सटीक जानकारी उपभोक्ता के पास नहीं होती है। फिर स्थानीय प्रशासन के लोग सिर्फ खाना-पूर्ति के लिए कभी-कभार छापेमारी करके अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर लेते हैं। यह शासन-प्रशासन का सामान्य दायित्व है कि अस्पताल में प्रयोग की जाने वाली वस्तुओं की कीमतें न्यायसंगत व पारदर्शी हों। निस्संदेह उपभोक्ता को वस्तुओं की वास्तविक कीमत की जानकारी दी जानी चाहिए।

स्कूली बच्चों को ज्ञान दीजिए अमानवीय प्रताड़ना नहीं

(लेखक - मनोज कुमार अग्रवाल)

भारत में शिक्षा का अधिकार कानून की धारा 17 स्कूलों में बच्चों को किसी भी तरह के शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न को एक दंडनीय अपराध की श्रेणी में रखती है। इस के बावजूद कुछ शिक्षक बच्चों के साथ अमानवीयता की हद तक शारीरिक मानसिक प्रताड़ना करने से बाज नहीं आ रहे हैं। स्कूलों में शिक्षकों द्वारा बच्चों की पिटाई और शारीरिक दंड एक गंभीर और गैर-कानूनी समस्या है, जिसपर विश्व स्वास्थ्य संगठन जैसी वैश्विक संस्थाएं भी चिंता जता चुकी हैं। हाल ही में ऐसी की घटनाएं सामने आई है जिनमें शिक्षकों की अमानवीयता और निर्दयता भरी पिटाई के कारण मासूम बच्चों की मौत हो गई अथवा वह गंभीर रूप से घायल हो गए।

हाल ही में आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के लिटिल गार्डन स्कूल में 20 अगस्त 2026 को होमवर्क पूरा न करने पर एक 6 साल के छात्र प्रणय तेजा की टीचर की कथित पिटाई और थप्पड़ मारने के बाद क्लासरूम में गिरकर मौत हो गई।दरअसल बच्चे ने होमवर्क पूरा नहीं किया था, जिसके बाद टीचर ने उसे डांटा और थप्पड़ मारा। क्लासरूम में लगे सीसीटीवी फुटेज में सामने आया कि थप्पड़ मारने और प्रताड़ित करने के कुछ ही पलों बाद बच्चा बेहोश होकर गिर पड़ा। बच्चे को तुरंत किंग जॉर्ज अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिवार का आरोप है कि डर और दहशत की वजह से उसे हार्ट अटैक आया। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम का इस घटना से सम्बद्ध वीडियो पूरे देश में वायरल हुआ, जिसमें एक प्राइवेट स्कूल की शिक्षिका बच्चे को डांटती और थप्पड़ मारती नज़र आ रही थी। उसके बाद बच्चे को कटे पेड़ की तरह गिरते देखा गया। बताते हैं कि होमवर्क पूरा न करने पर टीचर ने एलकेजी के छह वर्षीय छात्र प्रणय तेजा को पहले बुरी तरह डांटा और फिर उसे जोर से थप्पड़ मारा, जो उसे एक शॉक की तरह लगा। सीसीटीवी कैमरे की पुलिस द्वारा हासिल रिकॉर्डिंग में बच्चे की पिटाई और जमीन पर गिरने का दृश्य स्पष्ट दिखाई दे रहा था। बच्चे को अस्पताल ले जाया गया। जहां बताया गया है कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। इस घटना के बाद व्यापक विरोध प्रदर्शन भी हुए। अभिभावकों का आरोप है कि बच्चा घर से स्वस्थ स्थिति में स्कूल के लिए निकला था। उसे कोई रोग भी नहीं था। बाकायदा उसने स्कूल जाने की खुद जिद की। उसके पिता के अनुसार उनका परिवार एक तीर्थयात्रा पर गया था, जिसकी वजह से वह होमवर्क नहीं कर सका। इसके बाद टीचर के खिलाफ कार्रवाई और निजी स्कूलों में छात्रों की सुरक्षा बढ़ाने और संवेदनशील व्यवहार की मांग तेज हुई। वहीं दूसरी ओर स्कूल प्रशासन ने दलील दी कि खेल के मैदान में गिरने की वजह से बच्चे की जान गई। बताया जाता है कि स्कूल में कोई खेल का मैदान था ही नहीं। पूरी दुनिया में ऐसे तमाम अध्ययन व शोध निष्कर्ष सामने आ चुके हैं कि स्कूली बच्चों का किसी भी तरह शारीरिक व मानसिक उत्पीड़न नहीं किया जाना चाहिए। यह न केवल शिक्षकों का शैक्षिक दायित्व है बल्कि वे इसके लिये कानूनी रूप से भी बाध्य हैं। लेकिन विडंबना यह है कि शिक्षकों ने जाने क्यों मान लिया है कि किसी छात्र की गलती को दंडित या प्रताड़ित करके ही सुधारा जा सकता है। कहीं न कहीं यह शिक्षकों में धैर्य व तार्किक सोच की कमी को भी दर्शाता है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी पिछले दिनों ऐसी ही घटना सामने आई। वहां विनोद नगर में एक सरकारी स्कूल की ग्यारह साल की छात्रा की सजा दिए जाने के बाद मौत हो गई। उसका कसूर सिर्फ इतना था कि वह क्लास में किताब लाना भूल गई। शिक्षिका ने उसे क्लास के पीछे हाथ ऊपर करके खड़े होने की सजा दी। कक्षा में इस तरह काफी देर तक खड़े रहने और अपमान से आहत होने के बाद उसकी तबीयत खराब हो गई। उसे इलाज के लिये अस्पताल ले जाया गया लेकिन बाद में उसकी मौत हो गई। मौजपुर जाफराबाद दिल्ली में एक प्ले स्कूल में 3 साल के मासूम बच्चे को एप्रन की डोरी से 3 घंटे तक कुर्सी से बांधकर बेरहमी से पीटा गया, थप्पड़ मारे गए और कान खींचे गए, जिससे बच्चे के कान के पर्दे सूज गए। अमरोहा में हाल ही में दसवीं कक्षा के एक छात्र को स्कूल यूनिफॉर्म न पहनने और बेंच न उठाने पर शिक्षक ने डंडे से बेरहमी से पीटा इसी तरह की अन्य घटना में फरीदाबाद के एक स्कूल में मामूली बात पर छात्रा को चार घंटे खड़े होने की सजा दी गई। घटना से आहत व अपमानित महसूस करके छात्रा ने स्कूल की छत से कूदकर जान दे दी। जालौन उत्तर प्रदेश में तीसरी कक्षा के 8 वर्षीय बच्चे को शिक्षक ने बेरहमी से पीटने के बाद दो घंटे तक बाथरूम में बंद रखा।

मध्यप्रदेश संस्कार पब्लिक स्कूल में मामूली कहासुनी के बाद प्रिंसिपल ने 8वीं कक्षा के छात्र को लात-घूंसों से पीटा और जमीन पर लिटाकर बेरहमी से प्रताड़ित किया। विचारणीय प्रश्न है कि प्रशिक्षित शिक्षक इस बात को समझने का प्रयास क्यों नहीं करते कि उन्हें छात्रों के साथ संवेदनशील व्यवहार करना चाहिए। वे क्यों नहीं समझते कि क्लास में सबके सामने दंडित किए जाने से बच्चे के कोमल मन-मस्तिष्क पर कैसा नकारात्मक असर पड़ेगा। शीर्ष अदालत ने सभी स्कूलों के शिक्षकों के लिए इस बाबत सभी दिशा-निर्देश स्पष्ट रूप से दे रखे हैं, लेकिन इसके बावजूद अप्रिय हो रहा है। यह दुर्भाग्यपूर्ण ही है कि कई शिक्षक इन कानूनी व नैतिक मापदंडों को ताक पर रखकर बच्चों को प्रताड़ित करते हैं। निस्संदेह, कोई भी शैक्षिक व्यवस्था किसी भी शिक्षक को निरंकुश व्यवहार करने और अपनी भड़ास निकालने की इजाजत नहीं देती। दरअसल, समय के साथ-साथ बच्चों में ऐसे भाव विकसित हो गए हैं कि वे कक्षा में सार्वजनिक रूप से अपमान व प्रताड़ना बर्दाश्त नहीं करते। समाज में एकल परिवार परंपरा के प्रचलन के बाद बच्चे अभिभावकों के ध्यान के केंद्र में आ गए हैं। संयुक्त परिवारों में बच्चे मान-अपमान के प्रति इतने ज्यादा संवेदनशील नहीं होते थे। लेकिन आज घर में अकेले होने के नाते मिलने वाले विशिष्ट व्यवहार की अपेक्षा बच्चा स्कूल में भी करता है। फलतः किसी दंड या ताड़ना को वह बेहद गंभीरता से लेता है। आपको पुनः बता दें कानूनन राइट आफ एजुकेशन एक्ट की धारा 17 के तहत भी स्कूलों में किसी भी प्रकार का शारीरिक या मानसिक उत्पीड़न पूरी तरह प्रतिबंधित है। इसके बावजूद, ऐसी घटनाएं बच्चों के विकास और शिक्षा व्यवस्था के काले चेहरे को उजागर करती हैं।

बच्चों पर हाथ उठाने वाले शिक्षकों पर भारतीय न्याय संहिता /भारतीय दंड संहिता और किशोर न्याय अधिनियम के तहत कानूनी और फौजदारी कार्रवाई की जा सकती है।क्या कदम उठाए जा सकते हैं?घटना की तुरंत स्थानीय पुलिस थाने में लिखित शिकायत या एफआईआर दर्ज कराई जानी चाहिए।ऐसी घटनाओं की शिकायत राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग या चाइल्डलाइन (नंबर- 1098) पर की जा सकती है।शिक्षा बोर्ड के नियमों के अनुसार स्कूल प्रशासन को भी आरोपी शिक्षक के खिलाफ सख्त विभागीय कार्रवाई करनी चाहिए। (लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं पिछले 40 वर्ष से लेखन और पत्रकारिता से जुड़े हैं) (यह लेखक के व्य क्तिगत विचार हैं इससे संपादक का सहमत होना अ निवार्य नहीं है)

अनमोल हैं कड़वे बोल

किसी ने कहा है कि अंधेरे में माचिस तलाशता हुआ हाथ, अंधेरे में होते हुए भी अंधेरे में नहीं होता, इस तलाश को अपने भीतर निरंतर जीवित रखना कोई साधारण बात नहीं है, परंतु जो लोग सफर की हदों को पहचानते हैं, जिन्हें हर मंजिल के बाद किसी नए सफर पर चल पड़ने की लत है, उनके भीतर से यह खोज कभी खत्म नहीं होती। अचूक शैली में, अपने क्रांतिकारी विचारों से लोगों को अपनी ही खोज के तौर तरीके बताने वाले राष्ट्रसंत मुनि तरुणसागर जी महाराज की वाणी सहज आकर्षण का विषय बन गई है। ऐसे समय में जब अपने हक में हर खुशी बटोर लेने की अदम्य लालसा लोगों को दुनिया के दुख दर्द से कोसों दूर ले जा रही है। मुनि श्री दुनिया को खुशी और गम की सही परिभाषा बता रहे हैं। यह सिर्फ संयोग नहीं है कि वे जहां भी पहुंचते हैं, सबसे पहले यही कहते हैं कि मैं कथा सुनाने नहीं जीवन की व्यथा सुनाने आया हूं। यह व्यथा घर-घर की कहानी है, जिसे एक बड़े आईने की शक्ल में सामने रखकर मुनि तरूण सागर जी पुकार कर कह उठते हैं कि इसे न तो ठुकराओ, न ही झुठलाने की कोशिश करो, बेहतर यही है कि इस व्यथा के बीच से ही जीवन का रस हासिल कर लो। मुनि तरुण सागर जी के बोल, सुनने वाले को भावित-प्रभावित तो करते ही हैं, उसे झकझोर कर भी रख देते हैं। उन्हें सुनते समय या पढ़ते समय आप अनुभव करते हैं कि आपकी अपनी जिंदगी एक धारावाहिक के रूप में आपकी आंखों के सामने तैरने लगी है। उनकी वाणी अतीत की जड़ता से उबारने और वर्तमान की लापरवाही के प्रति सचेत करने का काम करती है। वह आपके जख्मों को सहलाने के बदले यदि अधिक कुरदने की मुद्रा में दिख भी रही हो तो भी यह नहीं भूलना चाहिए कि मुनि श्री आपको स्थाई रूप से तंदुरुस्त बनाने का उद्यम कर रहे हैं। सूत्र शैली में संदेश देने वाले मुनि तरूण सागर जी को अपनी वाणी को कड़वे प्रवचन कहने पर इत्मीनान यदि है तो सिर्फ इसलिए कि वे जानते हैं, इंसान की प्रवृत्ति और कभी न बदलने की उसकी जिद इतनी कठिन और जटिल है कि सीधी उंगली से घी निकालना मुमकिन नहीं है। आज साहित्य, संस्कृति और समाज के हर मंच पर महिला जागृति या नारी विमर्श का दौर ही चल पड़ा है। मुनि तरूण सागर जी साफ शब्दों में कहते हैं कि समाज पुरुष प्रधान है, परंतु याद रखना चाहिए कि महिलाओं की भूमिका पुरुषों से भी बड़ी है। वे सत्य से मुंह मोड़ने या पीछे हटने वाले समाज को न सिर्फ जगाते हैं बल्कि अपने कड़वे बोल से कोसने में भी कोई गुरेज नहीं करते। सच के पाखंडी चेहरे को पहचानने वाली उनकी गहरी दृष्टि सजग करती हैं कि वास्तव में जो सत्य है उसे किसी बनावट की जरूरत नहीं है। संघर्ष में सत्य परेशान हो सकता है किन्तु पराजित नहीं होता। छोटी-छोटी बातों से जीवन का बड़ा अर्थ निकाल लेने वाले मुनि तरूणसागर जी के बोल सचमुच अनमोल हैं। एक और उदाहरण देखिए वे कहते हैं कि प्रभु को सात बातें अच्छी नहीं लगती घमंड से भरी आंखें, झूठ से भरी जुबान, बुराई की तरफ बढ़ते कदम, झूठी गवाही, बुरी सोच, भाई को भाई से लड़ाना और खून से सने हाथ। जरा सोचिए इन बातों में आज के मनुष्य और समाज का कौन सा ऐसा पक्ष है जो शेष होगा। इंसान का दोहरापन और दुनिया का बहुरूपियापन हो या हिंसा और आतंक की कीमत पर सब कुछ हासिल कर लेने की अंधी कोशिश, मुनि तरूण सागर जी इन हालातों को बेपरदा कर देते हैं। इसके विपरीत वे जीने की कला की सारी सूत्र भी सहज रूप से बता देते हैं। प्रदूषण के सारे खतरों में विचारों के प्रदूषण को सबसे बड़ा कहने वाले मुनि श्री इस समस्या को विचारों की शक्ति से ही दूर करने के रास्ते भी सुझाते हैं, आवश्यकता बस इतनी है कि सुने हुए को जीवन में उतारने की शक्ति श्रोता स्वयं अपने भीतर पैदा करें।

जब चुनाव आयोग ही दलों की पहचान तय करने लगे, तो लोकतंत्र किसके भरोसे?

(लेखक- सनत जैन)

भारत में चुनाव आयोग लोकतंत्र का प्रहरी है। संविधान ने निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए उसे असीम शक्तियां दे रखी हैं। संविधान ने उसे इसलिए स्वतंत्र बनाया था, वह निष्पक्ष चुनाव करा सके। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त टीएन शेषन के समय पर चुनाव आयोग की धाक सारी दुनिया और देश में थी। सत्तापक्ष और विपक्ष के सभी नेता चुनाव आयोग की कार्यवाहियों को लेकर हमेशा सजग रहते थे। उस समय सभी राजनीतिक दलों को समानता का अवसर मिले, इस बात का ध्यान चुनाव आयोग ने रखा था। आज सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या चुनाव आयोग केवल चुनाव कराने वाली संवैधानिक संस्था है? या केंद्र सरकार के इशारे पर काम करने वाली एक ऐसी संवैधानिक संस्था बन गई है जो सरकार के इशारे पर सरकार के लिए काम कर रही है? चुनाव आयोग अब राजनीतिक दलों के अस्तित्व, नाम और चुनाव चिन्ह का फैसला करने वाली ऐसी शक्ति बनता जा रहा है, जिसके निर्णय से किसी पार्टी की पूरी राजनीतिक पहचान बदल सकती है? हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कई वर्षों से मामले सुनवाई के लिए पड़े हैं। उन पर समय रहते सुनवाई नहीं होती है? एक तरह से वह भी केंद्र सरकार के दबाव पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। इस बात के आरोप अब न्यायपालिका पर भी लगने लगे हैं, जिसके कारण लोकतंत्र और चुनाव की निष्पक्षता को लेकर राजनीतिक दलों के साथ-साथ अब जनता का विश्वास भी खत्म होता हुआ दिख रहा है।

केंद्रीय चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति पिछले कई वर्षों से विवादों में है। यह मामला भी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। इस पर भी इतने लंबे समय तक सुनवाई न होना न्यायपालिका पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। पश्चिम बंगाल का ताजा घटनाक्रम इसी सवाल को और भी गंभीर बनाता है। विधानसभा चुनाव के दौरान टीएमसी और भाजपा के बीच में तरह-तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाए गए थे। टीएमसी को खत्म करने की धमकी एक राजनैतिक दल द्वारा दी गई थी। वह धमकी अब पूरी होती हुई नजर आ रही है। विधानसभा चुनाव के 1 महीने के अंदर 40 निर्वाचित विधायक और करीब 20 सांसद पार्टी छोड़कर एक ऐसी पार्टी में चले गए जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं था। केंद्र सरकार, पश्चिम बंगाल की विधानसभा और चुनाव आयोग द्वारा समय-समय पर जो निर्णय लिए गए हैं वह इशारा कर रहे हैं, केंद्र सरकार के इशारे पर टीएमसी और ममता बनर्जी पार्टी को खत्म करने के लिए सुनयोजित साजिश हो रही है। भारत के बड़े-बड़े वकील कानून की बड़ी-बड़ी किताबें लेकर हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग के चक्कर लगा रहे हैं। जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं द्वारा समय-समय पर जो निर्णय लिए जा रहे हैं, वह सभी को आश्चर्यचकित कर रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस के भीतर विवाद के बाद चुनाव आयोग ने मूल पार्टी का नाम और 'फूल-घास' चुनाव चिन्ह अंतरिम रूप से फ्रीज कर दिया है। मुख्यमंत्री द्वारा रिक्त सीट नंदीग्राम पर टीएमसी उम्मीदवार को जबरिया बैठा दिया गया। चुनाव आयोग ने दोनों गुटों को नए नाम और नए चिन्ह दे दिए हैं।

पिछले विधानसभा चुनाव में मतगणना में हुई गड़बड़ी को लेकर ममता बनर्जी ने शिकायत दर्ज कराई थी, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। यह माना जा रहा है, नंदीग्राम में हुई गड़बड़ी का भेद न खुल जाए, इसलिए ममता बनर्जी की पार्टी का चुनाव चिन्ह ही सीज कर दिया गया है। ममता बनर्जी के गुट को 'ममता ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस' और फुटबॉल खिलाड़ी का चिन्ह मिला है। चुनाव आयोग का यह अंतिम फैसला नहीं है। सवाल अंतिम फैसले से भी बड़ा है। जिस पार्टी को उसके संस्थापक नेतृत्व ने बनाया, उसे एक ही झटके से खत्म कर दिया गया। जिस नाम और चिन्ह के साथ उसने कई चुनाव लड़े। 3 दशकों तक चुनाव लड़े। मतदाताओं ने वर्षों तक जिस चुनाव चिन्ह को पहचान दी। कुछ निर्वाचित प्रतिनिधियों के अलग हो जाने पर क्या उसकी राजनीतिक पहचान पर रोक लगाई जा सकती है? यह निर्णय इसी तरह का हुआ कि अब आप अपने पुराने नाम का इस्तेमाल नहीं करके नए नाम से अपनी पहचान बनाओ। क्या किसी का इस तरह से नाम बदला जा सकता है?

यही विवाद महाराष्ट्र में शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधायकों और सांसदों के दल बदल के समय सामने आया था। मूल पार्टी ने दल बदल कानून के तहत सदस्यता खत्म करने का आवेदन दिया था। उस पर कोई फैसला नहीं हुआ। राजनीतिक दलों के विभाजन और निर्वाचित विधायकों-सांसदों के दूसरे दल में जाने के बाद यह प्रश्न लगातार उठता रहा है। पिछले एक दशक में जितने भी दल बदल हुए हैं, इसका फायदा भारत के एक ही राजनीतिक दल को मिला है, जो केंद्र की सत्ता में बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में जो दलील रख रहे हैं, उसके जरिये उन्होंने दल बदल कानून की हर परत को उजागर किया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस भी जारी किया है।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

हीरो मोटर्स आईपीओ को निवेशकों का जोरदार रिस्पॉन्स

मुंबई ।

हीरो मोटर्स के इनीशियल पब्लिक ऑफर (आईपीओ) को निवेशकों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है, जो तीसरे और आखिरी दिन कुल 7.01 गुना सब्सक्राइब होकर बंद हुआ। हालांकि, ग्रे मार्केट में कंपनी के शेयर के प्रति उत्साह ठंडा पड़ा है और इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम शून्य पर पहुंच गया है, जिससे लिस्टिंग के फ्लैट रहने के संकेत मिल रहे हैं। यह इश्यू तीसरे और आखिरी दिन कुल 7.01 गुना सब्सक्राइब हुआ। गैर-संस्थागत निवेशकों ने 10.47 गुना और खुदरा निवेशकों ने 8.62 गुना बोलियां लगाईं, जबकि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स का हिस्सा 1.59 गुना भरा। हालांकि, अनलिस्टेड मार्केट में हीरो मोटर्स के आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम शून्य पर है, जो 84 रुपए के इश्यू प्राइस पर फ्लैट लिस्टिंग का संकेत देता है। 1,000 करोड़ रुपए के इस आईपीओ से मिली रकम का इस्तेमाल कर्ज चुकाने, प्लांट की क्षमता बढ़ाने और रणनीतिक अधिग्रहण में होगा। कंपनी की आय वित्त वर्ष 2026 में 9 फीसदी और मुनाफा 26 फीसदी बढ़ा है। पावरट्रेन सॉल्यूशंस बनाने वाली हीरो मोटर्स के शेयरों का आवंटन 21 सितंबर 2026 और लिस्टिंग 23 सितंबर 2026 को संभावित है।

चंडीगढ़ में भारत टैक्सी की हुई शुरुआत

चंडीगढ़ ।

चंडीगढ़ में एक ऐतिहासिक पहल के तहत देश की पहली सहकारी मॉडल पर आधारित ऑनलाइन सवारी सेवा 'भारत टैक्सी' का औपचारिक आगाज किया गया। पंजाब के राज्यपाल एवं केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने डिजिटल माध्यम से इसका उद्घाटन किया और इसके उपरांत 'भारत टैक्सी' के वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। चंडीगढ़ प्रशासन के सहकारिता विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोल और कृष्ण पाल गुर्जर भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम में चंडीगढ़ प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ भारत टैक्सी के प्रतिनिधि, सहकारी क्षेत्र के सदस्य और बड़ी संख्या में चालक-सदस्य भी शामिल हुए। एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि चंडीगढ़ में इस सेवा की शुरुआत प्रौद्योगिकी आधारित परिवहन क्षेत्र में सहकारी मॉडल के विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो चालकों को सशक्त बनाएगी और उपभोक्ताओं को विश्वसनीय सेवा प्रदान करेगी।

चंडीगढ़ में सीएनजी-पीएनजी हुई सस्ती, त्योहारी सीजन से पहले प्रशासन का बड़ा तोहफा

- प्राकृतिक गैस पर वैट 12.5 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी किया गया

चंडीगढ़ ।

केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में त्योहारी सीजन से पहले आम जनता को बड़ी राहत मिली है। प्रशासन ने कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस (सीएनजी) और पाइप वाली रसोई गैस (पीएनजी) पर लगने वाले वैल्यू एडेड टैक्स (वेट) को 12.5 फीसदी से घटाकर सीधे 5 फीसदी कर दिया है। वैट की दर में 7 फीसदी से अधिक की इस ऐतिहासिक कटौती से शहर में लाखों उपभोक्ताओं को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा। ये नई दरें हाल ही में लागू हो गई हैं, जिससे ईंधन की कीमतें तुरंत प्रभावी हुई हैं। इस महत्वपूर्ण कटौती के परिणामस्वरूप, घरेलू पीएनजी की कीमतों में लगभग 3.42 रुपये प्रति एससीएम तक की कमी आने का अनुमान है। फिलहाल चंडीगढ़ में घरेलू पीएनजी की कीमत लगभग 54.70 रुपये प्रति एससीएम है। इसी तरह, वाहनों में इस्तेमाल होने वाली सीएनजी गैस की खुदरा कीमतों पर भी इसका असर दिखेगा, जिससे वाहन चालकों और ऑटो-कैब ऑपरेटरों को सीधा फायदा होगा। चंडीगढ़ प्रशासन का यह कदम दोहरे उद्देश्य से प्रेरित है। पहला शहर में प्रदूषण के स्तर को कम करना और इसके लिए लोगों को पर्यावरण के अनुकूल ईंधन जैसे सीएनजी और पीएनजी अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना। दूसरा, प्राकृतिक गैस आपूर्ति करने वाली कंपनियों के लिए शहर में नैचुरल गैस नेटवर्क का विस्तार करना और बुनियादी ढांचे को मजबूत करना आसान होगा।

प्रशासन ने शहर के लगभग 1.70 लाख घरों को पीएनजी कनेक्शन से जोड़ने का लक्ष्य रखा है। सस्ती गैस होने से लोग पारंपरिक एलपीजी सिलेंडरों को छोड़कर पीएनजी की ओर तेजी से आकर्षित होंगे। गौरतलब है कि वैट एक अप्रत्यक्ष कर है जो वस्तु के उत्पादन से लेकर ग्राहक तक पहुंचने के हर चरण पर लगाया जाता है। हालांकि भारत में 1 जुलाई 2017 से अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी लागू हो गया है, भारतीय संविधान के नियमों के अनुसार पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस (जैसे सीएनजी और पीएनजी) को अभी भी जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। यही कारण है कि इन पर राज्य स्तर पर वैट लागू होता है, जिसे अब चंडीगढ़ प्रशासन ने घटाकर नागरिकों को बड़ी राहत प्रदान की है।

शेयर बाजार में सप्ताह भर रही उठापटक, फेड और कच्चे तेल ने बढ़ाई चिंता

वैश्विक दबाव में संघर्ष करता रहा शेयर बाजार, निवेशकों ने संभाली सतर्कता

मुंबई ।

सितंबर 2026 के मध्य में भारतीय शेयर बाजार ने एक अत्यधिक अस्थिर सप्ताह का अनुभव किया। वैश्विक बॉन्ड प्रतिफल और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के साथ-साथ अमेरिकी फेडरल रिजर्व के नीतिगत फैसलों की अनिश्चितता ने निवेशकों को लगातार सतर्क रखा। शुरुआती तेज उछाल के बावजूद बाजारों ने अक्सर अपनी बढ़त गंवाई और सप्ताह भर अस्थिरता बनी रही, जिससे कोई स्पष्ट दिशा नहीं मिल पाई। बीते सप्ताह सोमवार को गणेश चतुर्थी के अवसर पर शेयर बाजार बंद रहने की वजह से बाजार में केवल चार दिन ही कारोबार हुआ। सप्ताह की शुरुआत जोरदार तेजी के साथ हुई। मंगलवार को सेंसेक्स 200 अंक से अधिक चढ़कर 75,005.46 पर और निफ्टी 23,450 के स्तर को पार कर गया।

सूचना प्रौद्योगिकी सूचकांक में 3 फीसदी से अधिक की मजबूत तेजी दर्ज की गई, जिसने वैश्विक चुनौतियों को धता बताया। हालांकि यह शुरुआती उत्साह ज्यादा देर तक नहीं टिक सका। बाजार ने अपनी सारी बढ़त गंवा दी और भारी गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 778 अंक से अधिक टूटकर 74,003.82 पर और निफ्टी 23,118.60 पर आ गया। विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने शुद्ध आधार पर 2,977.86 करोड़ रुपये के शेयर बेचे, जो गिरावट का एक प्रमुख कारण था। मंगलवार की भारी गिरावट के बाद बुधवार को बाजार में वैल्यू बाइंग के कारण शुरुआती उछाल दर्ज किया गया। सेंसेक्स 244 अंक और निफ्टी 77 अंक चढ़कर कारोबार कर रहा था। हालांकि, कच्चे तेल की ऊंची कीमतें और अमेरिकी फेडरल रिजर्व के फैसले से पहले बाजार में सतर्कता बनी रही। दिन के अंत में सेंसेक्स 332.63 अंक बढ़कर 74,336.45 पर और निफ्टी 99 अंक चढ़कर 23,217.60 पर बंद हुआ। गुरुवार को भी बाजार में शुरुआती गिरावट के बाद तेजी लौटी, लेकिन फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरें बढ़ाने और मौद्रिक नीति में सख्ती के संकेत के बाद बाजार लगभग सपाट बंद हुए। सेंसेक्स 21.86 अंक गिरकर 74,314.59 पर और निफ्टी मामूली 53 अंक बढ़कर 23,270.60 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के 22,569 करोड़ रुपये के आईपीओ को पहले दिन 39 फीसदी सदस्यता मिली।

कृषि में नवाचार से उपभोक्ताओं की सुरक्षा से समझौता नहीं होना चाहिए- एफएसएसएआई

नई दिल्ली ।

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) की एक प्रमुख अे धिकारी ने कृषि क्षेत्र में नवाचार के महत्वपूर्ण पहलुओं पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि खेती में नवाचार का मकसद केवल फसल की पैदावार बढ़ाना नहीं, बल्कि उपभोक्ताओं की सुरक्षा और टिकाऊपन सुनिश्चित करना भी होना चाहिए। उन्होंने भारतीय कृषि-रसायन महासंघ की 9वीं सालाना आम बैठक में कहा कि नवाचार और विनियमन को प्रतिद्वंद्वी के बजाय सहयोगी के रूप में देखा जाना चाहिए।

उन्होंने स्पष्ट किया कि नवाचार को किसी खाद्य उत्पाद की सुरक्षा को कम करने के तरीके के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए; इसके बजाय, इसका उद्देश्य ग्राहकों के लिए सुरक्षा का स्तर बढ़ाना होना चाहिए। उन्होंने कहा कि कीटनाशकों के अवशेषों की सीमा वैज्ञानिक सबूतों, जोखिम-आधारित तरीकों और निगरानी पर आधारित होनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि सुरक्षा मानकों को कम करने के बजाय, फसलों के इस्तेमाल के बाद नए या उभरते हुए दूषित पदार्थों का पता लगाने के तरीके खोजने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। नवाचार हमेशा अच्छा होता है और यह हमेशा होना चाहिए, लेकिन उपभोक्ता सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता।

टाटा और नेक्सपेरिया ने की साझेदारी, भारत में बनेंगी पावर कंट्रोल चिप्स

एम्स्टर्डम ।

डच सेमीकंडक्टर (चिप) निर्माता नेक्सपेरिया ने भारतीय दिग्गज टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ भारत में कंप्यूटर चिप्स के निर्माण और पैकेजिंग के लिए एक महत्वपूर्ण साझेदारी की घोषणा की है। यह कदम चीनी मूल कंपनी विंगटेक से नेक्सपेरिया के अलगाव को और मजबूत करेगा, जो भारत के सेमीकंडक्टर क्षेत्र में एक नया अध्याय जोड़ रहा है। नेक्सपेरिया और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स मिलकर नेक्सपेरिया के पावर कंट्रोल चिप्स का उत्पादन करेंगे। ये चिप्स गुजरात के धोलेरा में टाटा के 11 अरब डॉलर के निर्माणाधीन संयंत्र में बनाए जाएंगे। कंपनियां असम के जागीरोड में टाटा की पैकेजिंग सुविधा में चिप्स की परीक्षण (टेस्टिंग) और असेंबलिंग (जोड़ना) में भी सहयोग करेंगी। हालांकि, वित्तीय शर्तों का खुलासा नहीं किया गया है, दोनों भविष्य की तकनीक विकसित करने में भी मिलकर काम करेंगे।

टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के एक अे धिकारी ने इस व्यापक साझेदारी को भारत में एक विश्व-स्तरीय, एकीकृत सेमीकंडक्टर विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। नेक्सपेरिया साधारण चिप्स का एक प्रमुख निर्माता है।

यह साझेदारी विंगटेक से नेक्सपेरिया के अलगाव को

मजबूत करती है, जो डच सरकार के हस्तक्षेप से शुरू हुआ था। बीजिंग ने पहले चिप्स निर्यात पर प्रतिबंध लगाकर जवाबी कार्रवाई की थी।

डच अदालत ने विंगटेक से नियंत्रण छीन लिया है, और टाटा के साथ इस साझेदारी को नेक्सपेरिया के मौजूदा प्रबंधन बोर्ड ने मंजूरी दी है।

मालदीव ने भारत का 15 करोड़ डॉलर का ट्रेजरी बिल चुकाया

पिछले पांच वर्षों का करीब 4.5 करोड़ डॉलर का ब्याज भारत सरकार ने वहन किया

नई दिल्ली ।

मालदीव ने भारत से जुड़े 15 करोड़ डॉलर (लगभग 1250 करोड़ रुपये) के ट्रेजरी बिलों का भुगतान पूरा कर लिया है। विदेश मंत्रालय ने यह जानकारी देते हुए बताया कि अंतिम पांच करोड़ डॉलर की किस्त का निपटान 17 सितंबर को सफलतापूर्वक किया गया। खास बात यह है कि इन ट्रेजरी बिलों पर पिछले पांच वर्षों का करीब 4.5 करोड़ डॉलर का ब्याज भारत सरकार ने वहन किया।

विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता के अनुसार भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने 2019 में इन ट्रेजरी बिलों को खरीदा था, जिनकी अवधि छह बार एक-एक साल के लिए बढ़ाई गई।

मूल राशि मालदीव ने चुकाई, जबकि भारत ने ब्याज का भार उठाया।

भारत ने मालदीव की वित्तीय प्रणाली को सहयोग देने के लिए 3,000 करोड़ रुपये की मुद्रा विनिमय सुविधा और 35 करोड़ डॉलर के ट्रेजरी बॉन्ड भी खरीदे हैं, जो 2029 और 2030 तक वैध हैं।

यह भारत-मालदीव की दीर्घकालिक विकास साझेदारी का एक और प्रमाण है, जिसके तहत भारत आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति भी करता है।

बदलते वैश्विक परिदृश्य में प्रबंधन शिक्षा को अपना दायरा बढ़ाना होगा- सीईए

पारंपरिक कुशलता के बजाय लचीलेपन, गहन सोच और चरित्र को पाठ्यक्रम में शामिल करने की सलाह

नई दिल्ली ।

भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) वी अनंत नागेश्वरन ने प्रबंधन शिक्षा के लिए एक बड़े बदलाव का आह्वान किया है। नोएडा में 16वें 'इंडियन मैनेजमेंट कॉन्क्लेव' में उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), बढ़ती भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा और आपूर्ति श्रृंखला में आने वाले व्यवधानों के कारण दुनिया तेजी से बदल रही है। ऐसे में प्रबंधन संस्थानों को पारंपरिक तकनीकों से आगे बढ़कर छात्रों को इन नई वास्तविकताओं के लिए तैयार करना होगा। उन्हें केवल एआई केंद्रित विषयों को जोड़ने के बजाय अपने पाठ्यक्रम में समझदारी, मुश्किल हालात से उबरने की क्षमता, गहरी सोच और चरित्र को केंद्र में रखना चाहिए। नागेश्वरन ने स्पष्ट किया कि पारंपरिक रूप से प्रबंधन का जोर लीन ऑपरेशन, जस्ट-इन-टाइम सिस्टम और एकल-स्रोत आपूर्ति श्रृंखला जैसी कुशलता पर था, लेकिन वैश्विक झटकों के कारण अब ये मॉडल कमजोर पड़ रहे हैं।

उन्होंने कहा कि प्रमुख शक्तियों के बीच बढ़ती होड़ और आपूर्ति व्यवस्थाओं को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने के कारण प्रबंधकों को अब अतिरिक्त क्षमता बनाने, विकल्पों को बनाए रखने और संगठनों में मुश्किल हालात से उबरने की क्षमता विकसित करने की आवश्यकता है, भले ही इससे लागत बढ़ जाए।

नागेश्वरन के अनुसार, बिना किसी रुकावट वाली कुशलता और एकल-स्रोत वैश्विक आपूर्ति व्यवस्था अब खत्म हो चुकी है। यह कम से कम एक पीढ़ी तक वापस नहीं आएगी। उन्होंने जोर दिया कि जिन प्रबंधकों को केवल संतुलन साधने और लागत कम रखने के लिए प्रशिक्षित किया गया था, उन्हें अब एक पूरी तरह बदली हुई दुनिया का सामना करना पड़ रहा है। नागेश्वरन की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब हाल ही में भू-राजनीतिक तनावों जैसे होर्मुज स्ट्रेट में व्यवधानों ने भारतीय व्यवसायों को आपूर्ति स्रोतों और रणनीतियों पर पुनर्विचार करने पर मजबूर किया है। सीईए ने भारतीय प्रबंधन संस्थानों से आग्रह किया कि वे पश्चिमी मॉडलों की नकल करने के बजाय अपनी अर्थव्यवस्था की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने वाले ढांचे विकसित करें।

ईंधन कीमतों में स्थिरता जारी, विंडफॉल टैक्स कटौती बेअसर

- पेट्रोल-डीजल के दाम नहीं बदले, सरकारी तेल कंपनियां रोज सुबह 6 बजे करती हैं संशोधन

नई दिल्ली ।

देशभर में पेट्रोल और डीजल की कीमतें शनिवार को लगातार स्थिर बनी रहीं। सरकारी तेल विपणन कंपनियों ने शे निवार को दरों में कोई बदलाव नहीं किया। हालांकि, सरकार ने हाल ही में पेट्रोल और डीजल के निर्यात पर लगने वाले विंडफॉल टैक्स में कटौती की थी, लेकिन इसका घरेलू उपभोक्ताओं के लिए कीमतों पर कोई सीधा असर नहीं पड़ा है। इस बीच, पेट्रोल पंप डीलर्स अब यूपीआई लेनदेन पर लगने वाले नए शुल्क को लेकर अपनी चिंताएं जाहिर कर रहे हैं। सरकार ने पेट्रोल पर निर्यात शुल्क में 1 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 5 रुपये प्रति लीटर की कटौती की थी। साथ ही एटीएफ पर भी 4 रुपये प्रति लीटर की राहत दी गई थी। यह कदम हालांकि घरेलू कीमतों पर सीधा असर नहीं डालेगा। प्रमुख शहरों जैसे दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपये और डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर पर स्थिर है। दूसरी ओर, पेट्रोल पंप डीलर अगले महीने से लागू होने वाले यूपीआई ट्रांजैक्शन चार्ज से छूट की मांग कर रहे हैं। डीलरों का कहना है कि उनका मार्जिन पहले से ही कम है और वे इस अतिरिक्त खर्च को वहन नहीं कर सकते। उन्होंने चेतावनी दी है कि वे 2,000 रुपए से अधिक के यूपीआई भुगतानों को स्वीकार करने से मना कर सकते हैं। इससे ग्राहकों को नकदी या कार्ड का रुख करना पड़ सकता है, जो डिजिटल इंडिया के लिए चुनौती होगा।

बोर्डरूम विवाद से टाटा ग्रुप का मार्केट कैप 39,000 करोड़ घटा

मुंबई ।

टाटा समूह की कंपनियों के शेयरों में शुक्रवार को खासी गिरावट दर्ज की गई, जिससे समूह का बाजार पूंजीकरण करीब 39,000 करोड़ रुपये घट गया। यह गिरावट समूह के शीर्ष नेतृत्व में चल रही खींचतान का सीधा परिणाम है, जहां टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन नोएल टाटा ने एन चंद्रशेखरन को तीसरे कार्यकाल के लिए फिर से नियुक्त करने के बोर्ड प्रस्ताव को अवैध करार दिया है। इस शीर्ष-स्तरीय खींचतान ने निवेशकों की चिंता बढ़ा दी है। गुरुवार को टाटा संस की बोर्ड बैठक में एन चंद्रशेखरन को अध्यक्ष के रूप में तीसरे कार्यकाल के लिए नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। हालांकि, टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन नोएल टाटा ने इस पुनर्नियुक्ति की वैधता पर सवाल उठाते हुए इसे अवैध करार दिया।

शीर्ष नेतृत्व में इस खींचतान का असर आज समूह के शेयरों पर साफ दिखा। जहां निफ्टी 50 में 0.33 फीसदी की मामूली बढ़त दर्ज की गई, वहीं निफ्टी टाटा 25 कैप सूचकांक 1.12 फीसदी नीचे बंद हुआ।

समूह की प्रमुख कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का शेयर 3.9 फीसदी गिरकर 2,105 रुपये पर बंद हुआ, जिससे कंपनी के बाजार पूंजीकरण में अकेले 30,754 करोड़ रुपये की कमी आई। टाटा केमिकल्स को भी भारी नुकसान हुआ और यह 11 फीसदी गिरकर 603.25 रुपये पर बंद हुआ। समूह की अन्य कंपनियों में टाटा टेक्नोलॉजीज 4.8 फीसदी और टाटा एलेक्सी 3.4 फीसदी नीचे बंद हुए।

क्यूईडी कैपिटल एडवाइजर्स में एक मैनेजिंग पार्टनर ने इस स्थिति पर टिप्पणी करते हुए कहा कि आम तौर पर शीर्ष नेतृत्व के बीच टकराव से बाजार में हलचल मच जाती है, लेकिन टाटा समूह एक ऐसा संस्थान है जो मजबूत बुनियाद पर टिका है, न कि किसी एक व्यक्तित्व पर। उन्होंने यह भी जोड़ा कि कारोबारी संचालन और आईपीओ को लेकर चल रहा यह बोर्डरूम टकराव कुछ समय के लिए अस्थिरता पैदा कर सकता है, लेकिन समूह की नींव इतनी मजबूत है कि वह इस मुश्किल दौर से निकल सकता है और लंबे समय में शेयरधारकों के मूल्यों को सुरक्षित रख सकता है। यह गिरावट निफ्टी आईटी सूचकांक में देखी गई व्यापक कमजोरी के अनुरूप भी थी, जो दिन के अंत में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला प्रमुख सूचकांक रहा।

कर्नाटक में दूध 8 रुपए महंगा करने की मांग, सरकार को 3 दिन का अल्टीमेटम

डेयरी किसानों का आरोप, उत्पादन लागत बढ़ने और हरे चारे की कमी से गहराया संकट

बैंगलूर।

कर्नाटक के उपभोक्ताओं को जल्द ही दूध के बढ़े हुए दाम का झटका लग सकता है। राज्य के दुग्ध उत्पादक संघों ने दूध की कीमतों में 8 रुपये प्रति लीटर की भारी वृद्धि की मांग की है, और इस संबंध में सरकार को तीन दिनों का अल्टीमेटम भी दे दिया है। यह मांग बेंगलुरु प्रेस क्लब में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाई गई। दुग्ध उत्पादक संघों का कहना है कि बढ़ती उत्पादन लागत और दूध के घटते उत्पादन ने उन पर भारी दबाव डाला है। बामुल, चामुल और मांड्या मिल्क जैसे बड़े मिल्क यूनियन इस मांग के पक्ष में हैं। उन्होंने सरकार से दूध उत्पादकों को दिए जाने वाले प्रोत्साहन (इंसेंटिव) में भी बढ़ोतरी की मांग की है। बामुल मिल्क यूनियन के प्रेसिडेंट ने बताया कि डेयरी एसोसिएशन पिछले आठ महीनों से सरकार के साथ बातचीत कर रहे हैं, लेकिन कोई हल नहीं निकला। डेयरी किसान इस समय गंभीर वित्तीय संकट से जूझ रहे हैं। कम बारिश के कारण हरे चारे की कमी है, वहीं पशु आहार और कच्चे माल की कीमतों में 25 फीसदी तक की बढ़ोतरी हो चुकी है। ट्रांसपोर्टेशन खर्च बढ़ने से दूध उत्पादन की कुल लागत काफी बढ़ गई है, जिससे किसानों के लिए मवेशी पालना मुश्किल हो रहा है। संघों ने चेतावनी दी है कि यदि तीन दिनों के भीतर कैबिनेट की बैठक बुलाकर फैसला नहीं लिया गया, तो वे विधान सौध तक विरोध मार्च निकालेंगे। यदि राज्य सरकार इस प्रस्ताव को मंजूरी दे देती है, तो नवरात्रि और दिवाली जैसे त्योहारों से ठीक पहले नंदिनी जैसे ब्रांड का दूध बेहद महंगा हो जाएगा। इससे न केवल रसोई का बजट गड़बड़ाएगा, बल्कि मिठाई और अन्य डेयरी उत्पादों की कीमतें भी आसमान छू सकती हैं।

टाटा संस में चंद्रशेखरन का कार्यकाल विस्तार, नोएल टाटा की आपत्ति

चेयरमैन की तीसरी नियुक्ति पर बोर्ड मेंबर्स का समर्थन, पर नोएल टाटा नहीं थे सहमत

नई दिल्ली ।

मुंबई में गुरुवार को हुई टाटा समूह की एक महत्वपूर्ण बैठक में एन चंद्रशेखरन का कार्यकाल तीसरी बार बढ़ा दिया गया है। टाटा संस के चेयरमैन के तौर पर अगले पांच साल तक वे समूह का नेतृत्व करते रहेंगे। हालांकि, इस फैसले पर टाटा परिवार के सदस्य नोएल टाटा ने आपत्ति जताई थी, लेकिन अन्य बोर्ड सदस्यों के पूर्ण समर्थन के बाद चंद्रशेखरन को दोबारा कमान सौंप दी गई। इस घटना ने दोनों अहम शख्सियतों की भूमिकाओं और उनके पारिश्रमिक में बड़े अंतर को भी उजागर किया है। टाटा समूह के भीतर यह चर्चा तेज है कि एन चंद्रशेखरन के कार्यकाल विस्तार से नोएल टाटा नाखुश हैं। बोर्ड में वोटिंग के दौरान नोएल टाटा ने अपनी असहमति स्पष्ट की। नोएल टाटा, रतन टाटा के सौतेले भाई और टाटा परिवार के अहम सदस्य हैं। वे टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन सहित समूह की कई कंपनियों में गैर-कार्यकारी भूमिकाओं में हैं। दूसरी ओर, एन चंद्रशेखरन पिछले 10 साल से टाटा संस के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के रूप में समूह का नेतृत्व कर रहे हैं और अब अगले 5 साल के लिए उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। दोनों के बीच मतभेद का सटीक कारण अज्ञात है, लेकिन उनकी भूमिकाओं और पारिश्रमिक में बड़ा अंतर है। आंकड़ों के अनुसार, नोएल टाटा को विभिन्न गैर-कार्यकारी बोर्ड भूमिकाओं के लिए सालाना करीब 4.5 से 5 करोड़ रुपये का पारिश्रमिक मिलता है। इसमें बोर्ड मीटिंग फीस और डायरेक्टर कमीशन शामिल हैं। वहीं, एन चंद्रशेखरन का सालाना पैकेज 135 से 155 करोड़ रुपये के बीच बताया जाता है, जिसमें बुनियादी वेतन के साथ कंपनी के प्रदर्शन से जुड़ा बड़ा कमीशन भी शामिल है। इस तरह, चंद्रशेखरन का पैकेज नोएल टाटा को मिलने वाले पारिश्रमिक से लगभग 27-30 गुना अधिक है। यह अंतर मुख्य रूप से उनकी भूमिकाओं में है- चंद्रशेखरन एक कार्यकारी चेयरमैन के तौर पर रोजाना के कारोबारी फैसले और रणनीति संभालते हैं, जबकि नोएल टाटा की भूमिका गैर-कार्यकारी सलाह और निगरानी तक सीमित है। जहां नोएल टाटा की संपत्ति कई स्रोतों के अनुसार 1,245 करोड़ से 12,600 करोड़ रुपये तक अनुमानित है (जो परिवार की होल्डिंग्स पर निर्भर करता है), वहीं चंद्रशेखरन का पैकेज उनकी कार्यकारी जिम्मेदारियों का सीधा परिणाम है।

आईसीआईसीआई बैंक ने वेबसाइट और नेट बैंकिंग के यूआरएल बदले

नई दिल्ली ।

आईसीआईसीआई बैंक के इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग करने वाले ग्राहकों के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। बैंक ने अपनी वेबसाइट और नेट बैंकिंग के वेब पते (यूआरएल) में बदलाव किया है।

यह कदम भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के नियमों के तहत उठाया गया है, जिसके तहत बैंक को अपने पुराने डोमेन को नए डॉटबैंकडाटइन डोमेन पर स्थानांतरित करना पड़ा है। बैंक द्वारा ग्राहकों को भेजी गई सूचना अनुसार, नेट बैंकिंग का पुराना पता रिटेलबैंकिंगडाटआईसीआईसीआईबैंकडॉटकॉम अब बदलकर रिटेलबैंकिंगडाटआईसीआईसीआईबैंकडॉटइन कर दिया गया है। इसी तरह, बैंक की मुख्य वेबसाइट आईसीआईसीआईडॉटबैंकडाटइन डोमेन पर उपलब्ध होगी।

यह बदलाव ग्राहकों के मौजूदा ग्राहक आईडी, पासवर्ड या बैंक खाते की जानकारी पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा।

ग्राहक अपने पुराने लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके ही नए नेट बैंकिंग पोर्टल पर आसानी से लॉग इन कर सकेंगे। उन्हें किसी भी प्रकार के नए पंजीकरण या नया लॉगिन बनाने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अतिरिक्त, बैंक ने यह भी सूचित किया है कि 19 सितंबर, 2026 को आईमोबाइल ऐप की सेवाएं कुछ घंटों के लिए निर्धारित रखरखाव के कारण बंद रहेंगी। यह एक पूर्व-निर्धारित कार्य है और ग्राहकों को इससे अवगत कराया गया है।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

जीव-जंतुओं की दुनिया के सबसे अनोखे सदस्य

दोस्तों जीव-जंतुओं की दुनिया बड़ी ही निराली है। इस दुनिया के बारे में हम जितना भी जानते हैं उतनी ही हमारी और जानने की ख्वाहिश बढ़ती चली जाती है। हमारी दुनिया में कई छोटे-बड़े जीव ऐसे हैं जिनकी खासियतें बड़ी ही अनोखी और निराली हैं। आज ऐसे ही कुछ जीवों से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। हम इन जीवों की खासियतें भी आपको बताएंगे। अगर आप उन लोगों में से एक हैं जिन्हें जीव-जंतुओं की दुनिया में घुसने में मजा आता है तो यकीन जानिए, ये आपके लिए ही है।

रोसी मेपल मोथ

ये उत्तरी अमेरिका में बहुतायत में पाया जाने वाला एक कीट है। आम बोलचाल में इसे रोसी मेपल मोथ कहा जाता है। वहीं वैज्ञानिक भाषा में इसे ड्रायोकैम्पा रुबीक्यूंडा कहा जाता है। ये रेशम का का कीट है। इसिलिए इसे फैब्रीसियस भी कहा जाता है। इस तस्वीर में दिखाई दे रहा ये कीट अपना एक पैर उठाए हुए है जिसे देखकर लग रहा है जैसे ये हैलो कर रहा है।

वॉम्बेट

ये बेहद अनोखा और बेहद प्यारा जीव इन दिनों बेहद खतरनाक हालात से जूझ रहा है। ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में इन दिनों बेहद भीषण आग लगी है जिसमें 50 करोड़ से भी अधिक जीव जलकर खाक हो गए हैं। ये एक छोटा वॉम्बेट है। वॉम्बेट के पैर और पूंछ इनके शरीर की तुलना में काफी छोटी होती है। इनका शरीर 1 मीटर तक लंबा हो जाता है। ये पहाड़ी, मैदानी और जंगली इलाकों में पाए जाते हैं।

सम्राट तामरीन

ये मूंछों वाला बंदर तामरीन बंदरों की कई प्रजातियों में से एक है। इसे सम्राट तामरीन कहा जाता है। कहा जाता है कि जर्मन सल्तनत के सम्राट विल्हेम द्वितीय की मूंछे भी इसी तरह की हुआ करती थी। इसिलिए इस तामरीन बंदर को सम्राट तामरीन कहा जाता है। ये बंदर अमेजन के जंगलों में बहुतायत में पाए जाते हैं।

स्कॉटिश भेड़

स्कॉटलैंड में बहुतायत में भेड़ पालन करने वाले किसान वास करते हैं। स्कॉटलैंड में इंसानों से ज्यादा भेड़ें रहती हैं। यहां के 15000 भेड़ फार्म्स में 70 लाख के आस-पास भेड़ें रहती हैं। किसान इन भेड़ों को दूध, ऊन और मांस के लिए पालते हैं। पिछले दिनों एक शीप फार्म से इस भेड़ की ये अनोखी तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी।

अमेरिका में कई किसान इन्हें पालते भी हैं।

एग्जेंन्थिक ब्लू इगुआना

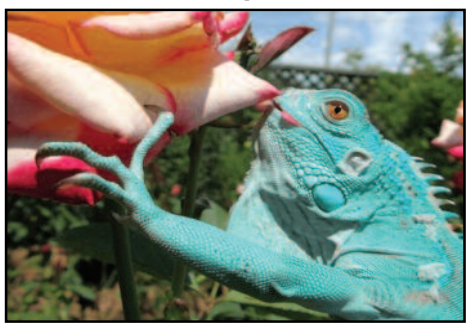

इगुआना एक प्रकार की छिपकली होती है। एग्जेन्थिक ब्लू इगुआना सभी प्रकार की इगुआना में सबसे खूबसूरत होती है। ये इतनी खूबसूरत होती है कि अमेरिका जैसे देशों में इसे लोग शौक से पालते भी हैं। अमेरिका में इसके पालने पर प्रतिबंध नहीं है और लोग इसे बाजार में बेच भी सकते हैं। गुलाब की खुशबू सूंघती इस इगुआना की तस्वीर काफी वायरल हुई थी।

रोशनी वाला पेड़

भारत में हिमालय के आसपास कुछ ऐसे पेड़-पौधे भी हैं, जो रात के घोर अंधकार में चमक उठते हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है, जैसे लाइट जल उठी हो। ऐसा ही एक पौधा सोम औषधि है। पूर्णिमा की रात से अमावस्या तक इसके सारे पत्ते गिर जाते हैं और यह रात को चमकता है। कुछ पेड़ हैं, जिनके तनों से विशेष किस्म का द्रव्य बहता है, यह द्रव्य अंधेरा होने पर चमकता है। मशरूम की भी कुछ किस्में ऐसी होती हैं, जो रात को चमक देती हैं।

कहां जाएं ध्रुवीय भालू

इनसानी दखल का असर अब ध्रुवीय भालू की जिंदगी पर पड़ने लगा है। बर्फीले आर्कटिक क्षेत्र के निवासी ये भालू गरम होते क्षेत्र के कारण अपने रहने के स्थान खोने लगे हैं। बर्फ पिघलने से इन्हें खाने के लिए भी ठीक से नहीं मिल पा रहा है। उस पर बड़ी कंपनियां लगातार उनके इलाके में घुसपैठ कर रही हैं, जिस कारण इन भालुओं को लगातार अपने रहने का ठिकाना बदलना पड़ रहा है। ऐसे में खाने की कमी को ये दूसरे भालुओं को मारकर पूरी कर रहे हैं। बड़े भालुओं का शिकार आमतौर पर मादा भालू या बच्चे बन रहे हैं। ऐसी घटनाएं पहले कभी-कभार ही होती थीं। इससे ध्रुवीय भालू के लुप्त होने का खतरा बढ़ गया है।

मेहुल की सेल्फी

नौवीं क्लास में पढ़ने वाले मेहुल को हाल ही में उसके मामा ने मोबाइल गिफ्ट में दिया था। इसकी भी एक वजह थी। मामा ने उससे वादा किया था कि अगर वह आठवीं क्लास में फर्स्ट आएगा तो वह उसे उसका मनचाहा गिफ्ट देंगे। मेहुल क्लास में फर्स्ट आया। उसके मामा ने भी उससे किया हुआ वादा निभाया।

'मेहुल.ओ.मेहुल। कहां हो तुम?' मां मेहुल को काफी देर से ढूंढ़ रही थीं, लेकिन वह कहीं नजर नहीं आ रहा था। जब मेहुल उन्हें अपने कमरे में भी नहीं दिखाई दिया तो वह सोच में पड़ गईं कि इतनी गर्मी में मेहुल बिना बताए कहां गया है। तभी उन्हें ख्याल आया कि एक बार छत पर जाकर भी देख लिया जाए। वैसे इस भरी दोपहर में उन्हें उसके छत पर होने की उम्मीद कम ही थी, लेकिन उनका मन नहीं माना। पर यह क्या! जैसे ही वह छत पर पहुंचीं तो देखा कि मेहुल छत पर खड़ा अपने नए मोबाइल से सेल्फी खींचने में व्यस्त है! वह सेल्फी में इतना खोया हुआ था कि उसे न तो मां की आवाज सुनाई दे रही थी और न ही उनके छत पर आने का पता था। मां ने उसके करीब जाकर उसकी पीठ पर थप्पड़ मारते हुए कहा, 'यह क्या कर रहे हो तुम इतनी धूप में?' तो वह चौंका। 'कुछ नहीं मां, बस यूं ही।' 'यूं ही क्या?' मां ने गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए कहा। 'मां, अपने इस नए मोबाइल से कुछ सेल्फी ले रहा था, दोस्तों को दिखाने के लिए।' 'क्या मतलब, क्या तुम्हें यह मोबाइल इतनी धूप में सेल्फी खींचने के लिए मिला है?' मां ने उसे डांटते हुए कहा। 'चलो नीचे, मां उसका हाथ पकड़ कर ले जाने लगीं।' मेहुल अनमने मन से मां के साथ चलने लगा।

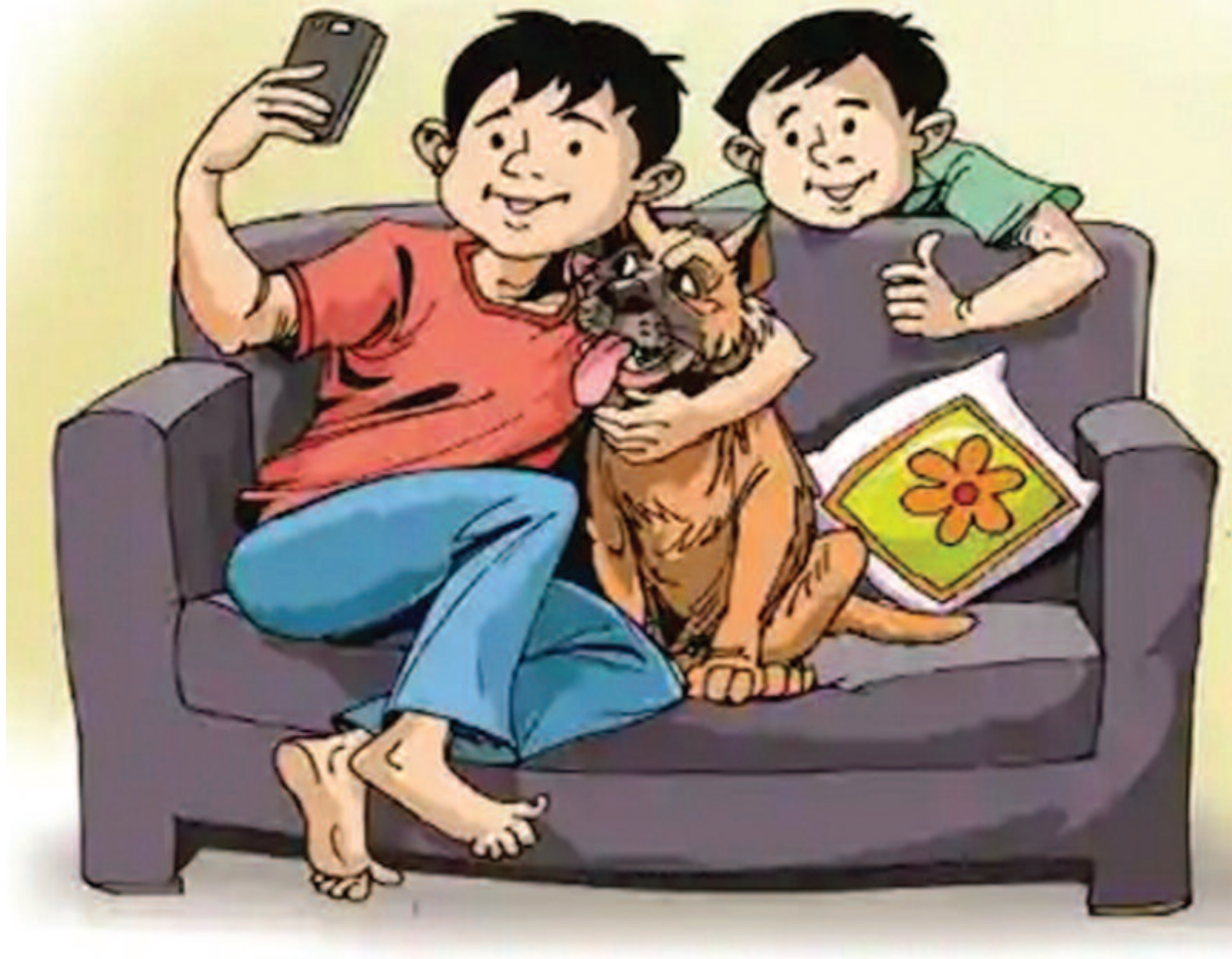

नौवीं क्लास में पढ़ने वाले मेहुल को हाल ही में उसके मामा ने मोबाइल गिफ्ट में दिया था। इसकी भी एक वजह थी। मामा ने उससे वादा किया था कि अगर वह आठवीं क्लास में फर्स्ट आएगा तो वह उसे उसका मनचाहा गिफ्ट देंगे। मेहुल क्लास में फर्स्ट आया। उसके मामा ने भी उससे किया हुआ वादा निभाया। मोबाइल पाकर मेहुल की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने अपने सभी दोस्तों को मोबाइल दिखाया और दिन भर उनके साथ सेल्फी का मजा लिया। देर शाम को जब वह घर आया तो मां ने उसे टोका भी, 'यह क्या बात हुई कि तुम नए मोबाइल के साथ दिन भर गायब रहे। न खाने-पीने की चिंता, न गर्मी की चिंता। कहीं बीमार हो गए तो स्कूल से छुट्टी लेनी पड़ेगी।' मां ने उसे ज्यादा नहीं डांटा, उन्हें लगा कि यह दो-तीन दिन का बुखार है, बाद में सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन सुबह रोज की तरह मेहुल उठा और तैयार होकर स्कूल जाने लगा। उसने अपने बैग में अपना नया मोबाइल भी रख लिया। मां ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया। उन्होंने उसके बैग से मोबाइल निकालते हुए कहा, 'तुम स्कूल पढ़ने जा रहे हो या मोबाइल पर बातें करने या फिर सेल्फी खींचने के लिए।' मां उसकी ओर गुस्से से देखते हुए मोबाइल लिए किचन में चली गईं। मेहुल गुस्से से पैर पटकते हुए स्कूल की ओर चल दिया। आज उसका मन क्लास में नहीं लग रहा था। उसे बस यही इंतजार था कि कब स्कूल की छुट्टी हो और वह घर जाकर अपने मोबाइल से तरह-तरह की सेल्फी ले। आखिर उसके इंतजार की घड़ी खत्म हुई। स्कूल की छुट्टी हो गई। घर पहुंचते ही मेहुल सीधा मां के पास पहुंचा और कहा, 'मां, मेरा मोबाइल कहां है?' मां ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, 'पहले कपड़े बदलो और खाना खा लो फिर तुम्हारा मोबाइल भी तुम्हें मिल जाएगा।' यह कहकर मां किचन की ओर चल दीं। मेहुल समझ गया कि अगर उसे मोबाइल चाहिए तो मां का कहना मानना ही पड़ेगा। उसने जल्दी से कपड़े बदल कर खाना खाया। मां ने उसका मोबाइल लाकर उसे दे दिया। मोबाइल देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जाते-जाते मां ने उसे हिदायत दे दी कि इस गर्मी में वह छत पर या बाहर न जाए। मेहुल ने मन ही मन सोचा, यह भी कोई बात हुई। घर पर भी कोई सेल्फी लेता है। असली मजा तो बाहर सेल्फी लेने में है। मोहित के डॉगी रॉकी के साथ या फिर राहुल के भैया की बाइक पर। सोसाइटी में बने स्वीमिंग पूल पर सेल्फी का तो अलग ही मजा आएगा। यह सोचकर मेहुल बाहर जाने लगा। मां ने उसे बाहर जाते हुए देखकर कहा, 'इस दोपहर में कहां जा रहे हो?' 'मां, मैं मोहित के घर जा रहा हूं, थोड़ी देर में आ जाऊंगा।' मां ने उससे कहा, 'जल्दी आ जाना। शाम को तुम्हारे मामा आने वाले हैं। हम सब उनके साथ बाहर घूमने जाएंगे।' 'पक्का मां, मैं जल्दी आ जाऊंगा।' यह कहकर मेहुल तेजी से मोहित के घर की ओर भागा।

मेहुल को देख मोहित खुश हो गया। मेहुल और मोहित दोनों मोबाइल से सेल्फी लेने लगे। तभी मेहुल को मोहित का डॉगी दिखाई दिया। उसने मोहित से कहा, 'क्यों न रॉकी के साथ सेल्फी ली जाए।' मोहित ने उसकी हां में हां मिलाई। फिर क्या था कि दोनों रॉकी के साथ सेल्फी लेने लगे। पहले तो रॉकी को भी उनके इस खेल में मजा आ रहा था लेकिन जल्दी ही वह उनकी हरकतों से उकता गया। वह एक-दो बार उन पर गुर्राया भी लेकिन उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। तभी सोफे पर बैठे मेहुल ने अपनी बगल में बैठे रॉकी को गर्दन से लगभग खींचते हुए अपने पास लाकर सेल्फी खींचनी चाही तो रॉकी भड़क गया और उसने मेहुल के हाथ पर काट लिया। मेहुल के मुंह से चीख निकल गई। मोहित की मम्मी बगल के कमरे से दौड़ी-दौड़ी आईं। रोते हुए मेहुल और खून से सना हुआ उसका हाथ देखकर वह घबरा गईं। उन्होंने जल्दी से उसके घाव को साबुन से धोया और उसे डॉक्टर के पास ले गईं। रास्ते में उन्होंने मोहित से पूछा, 'यह कैसे हुआ?' 'मां, रॉकी ने काटा है' मोहित ने कहा। 'ऐसे कैसे काट लिया, सच-सच बात बताओ?' 'मां, मेहुल रॉकी के साथ सेल्फी ले रहा था, तभी पता नहीं इसे क्या हुआ और इसने मेहुल को काट लिया।' 'तुम अपने सेल्फी के मजे में यह भूल गए कि तुम्हारी इन हरकतों से रॉकी को परेशानी हो रही है। उसे जब कुछ समझ नहीं आया होगा तो उसने मेहुल को काटकर अपना गुस्सा जता दिया।' मां ने नाराज होते हुए कहा।

डॉक्टर से पट्टी करवाने के बाद मेहुल घर पहुंचा तो उसे इस हालत में देखकर मां एकदम घबरा गईं लेकिन जब असली बात पता चली तो उसे मां की डांट भी खानी पड़ी। उसे समझ आ गया था कि काश उसने सेल्फी की बीमारी को अपने सिर पर चढ़ने नहीं दिया होता तो यह सब नहीं होता।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

संक्षिप्त समाचार

होर्मुज में ईरान का बड़ा एक्शन : टोगो के तेल टैंकर को बनाया निशाना, इलाके में बढ़ा तनाव

तेहरान, एजेंसी। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने शुक्रवार को कहा कि उन्होंने होर्मुज जलडमरूमध्य में टोगो के झंडे के नीचे चल रहे एक तेल टैंकर पर हमला किया। इसके बाद इलाके में तनाव बढ़ गया है। यह जानकारी ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी आईआरएनए के अनुसार है। अमेरिका और इस्राइल की ओर से फरवरी के अंत में ईरान पर हमला करने के बाद से तेहरान ने जलडमरूमध्य की प्रभावी नाकाबंदी कर रखी है। दरअसल, इस्लामी गणराज्य आवागमन के लिए शुल्क लगाना चाहता है और उन जहाजों पर हमला करता है, जिन पर वह अपने पसंदीदा मार्ग को दरकिनार करने का प्रयास करने का आरोप लगाता है। बयान में कहा गया है, 'टोगो के झंडे वाले तेल टैंकर 'ट्रेंड' को उस समय निशाना बनाया गया और हिरासत में लिया गया जब उसमें आग लग गई।' यह बयान महत्वपूर्ण जलमार्ग से अवैध रूप से गुजरने के प्रयास का जिक्र करते हुए दिया गया था। यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस ने गुरुवार को ओमान के खासब से 16 समुद्री मील (29.6 किमी) उत्तर-पूर्व में होर्मुज जलडमरूमध्य में एक सुरक्षा घटना की घोषणा की।यूकेएमटीओ ने शामिल पोत के बारे में कोई जानकारी नहीं दिया। इसके साथ ही यह स्पष्ट नहीं है कि क्या यह वही पोत है जिसका जिक्र रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने किया था।

अमेरिका के मिशिगन में ट्रेनिंग के दौरान एफ-16 क्रैश, पायलट अस्पताल में भर्ती

वाशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका के मिशिगन में सैन्य ट्रेनिंग के दौरान बड़ा हादसा हो गया। सैन्य ट्रेनिंग एक्सरसाइज के दौरान एफ-16 फाइटर जेट क्रैश हो गया। क्रैश होते ही आग लग गई और जेट पूरी तरह धूं-धूं कर जल उठा। गनीमत रही कि पायलट सुरक्षित इजेक्ट करने में कामयाब रहा, जिससे उसकी जान बच गई। फिलहाल, पायलट को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया है। पायलट का इलाज चल रहा है और उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। दरअसल, गुरुवार को मिशिगन के ग्रैंड ट्रैवर्स काउंटी में एक एफ-16 फाइटर जेट क्रैश हो गया। काउंटी के इमरजेंसी मैनेजमेंट विभाग ने बताया कि काउंटी रोड 633 के कुछ हिस्सों में लोगों को वहां से हटने का आदेश दिया गया है। टेक्सास नेशनल गार्ड के 149वें फाइटर विंग के एक प्रवक्ता ने पुष्टि की कि पायलट सुरक्षित बाहर निकल गया था और उसकी हालत स्थिर है। फिलहाल उसका इलाज चल रहा है। प्रवक्ता के अनुसार, क्रैश के समय यह विमान एक रूटीन ट्रेनिंग एक्सरसाइज में हिस्सा ले रहा था। मिशिगन में फाइटर जेट क्रैश होने के बाद हड़कंप मच गया। वहां आसपास मौजूद लोगों ने तेज धमाके की आवाज सुनी और आसमान में काले धुए का गुबार छा गया। एक चश्मदीद ने बताया कि क्रैश होने से पहले विमान बहुत नीचे उड़ रहा था। क्रैश के बाद, विमान से केमिकल लीक होने की खबरें आईं। शुरू में, लोगों को घर के अंदर रहने की सलाह दी गई थी, लेकिन बाद में मिशिगन पुलिस ने एक मील के दायरे में रहने वाले लोगों के लिए 'शेल्टर-इन-प्लेस' यानी घर के अंदर सुरक्षित रहने का आदेश जारी किया।

जापान में भालू मंत्री! परेशान होकर सरकार ने बनाया अलग मंत्रालय; कैबिनेट मिनिस्टर को जिम्मा

टोक्यो, एजेंसी। जापान में भालू के तांडव को देखते हुए सना तकाइची सरकार ने एक अलग मंत्रालय बनाने का फैसला लिया है. इस मंत्रालय के प्रमुख को कैबिनेट रैंक दिया जाएगा. मंत्रालय का काम भालुओं के हमले से लोगों को बचाना होगा. कंट्रोल को लेकर यह मंत्रालय आने वाले दिनों में एक रोडमैप तैयार करेगा. यह फैसला गुरुवार को कैबिनेट फेरबदल के दौरान लिया गया. ब्लूमबर्ग के मुताबिक जापान भालुओं के हमले से काफी परेशान है. इसको लेकर लगातार लोगों की शिकायत आ रही थी. अब सरकार ने इसके कंट्रोल के लिए अलग से मंत्रालय बनाने का फैसला किया है. जापान सरकार ने कैबिनेट फेरबदल में सत्ताधारी दल के सांसद हिरोयोशी सासागावा को भालू कंट्रोल मामलों के विभाग का नया मंत्री नियुक्त किया है. उन्हें पर्यावरण मंत्रालय की भी जिम्मेदारी दी गई है. इसके अलावा वे आपातकालीन परमाणु विभाग का कामकाज भी देखेंगे. नए फेरबदल में वित्त, रक्षा, वाणिज्य और विदेश मंत्रियों के कामकाज में कोई बदलाव नहीं किया गया है. तकाएची का कहना है कि यह कैबिनेट का पुनर्गठन है।

अमेरिका का नया नियम : 30 पार कर चुके सैनिकों की टेस्टोस्टेरोन जांच अब जरूरी, पेंटागन ने जारी की गाइडलाइन

वॉशिंगटन , एजेंसी। पेंटागन ने 30 साल और उससे ज्यादा उम्र के अमेरिकी सैनिकों के लिए टेस्टोस्टेरोन की कमी की अनिवार्य जांच शुरू करने के लिए नई क्लिनिकल गाइडलाइन जारी की हैं। इसके साथ ही, इलाज के लिए सीमाएं तय की हैं। वहीं, सिर्फ परफॉर्मेंस बेहतर बनाने के लिए इस हार्मोन का इस्तेमाल करने के खिलाफ चेतावनी भी दी है।

रक्षा स्वास्थ्य एजेंसी ने क्या निर्देश जारी की है : रक्षा स्वास्थ्य एजेंसी ने 17 सितंबर को गाइडेंस जारी की। यह जुलाई के उस निर्देश के तहत पुरुष सैन्य कर्मियों के लिए स्क्रीनिंग और इलाज की एक जैसी प्रक्रियाएं तय करती है, जिसमें सक्रिय और आरक्षित कर्मियों शामिल हैं। 30 साल से कम उम्र के लोग स्क्रीनिंग के लिए अनुरोध कर सकते हैं। पेंटागन ने इस पहल को युद्ध की तैयारियों से जोड़ा।

पेंटागन की ओर से क्या कहा गया : पेंटागन के मुख्य प्रवक्ता ने एक बयान में कहा, 'विभाग एक ऐसी तैयार और घातक लड़ाकू फोर्स बनाने और उसे बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, जो युद्ध के मैदान में दबदबा बनाने और ताकत के जरिए शांति हासिल करने में सक्षम हो।' हालांकि, क्लिनिकल दस्तावेज में पुष्टि की गई कमी का इलाज करने और युद्ध के मैदान में बेहतर प्रदर्शन के लिए टेस्टोस्टेरोन देने के बीच स्पष्ट अंतर बताया गया है।

इसमें कहा गया है, 'मौजूदा सबूतों के आधार पर, किसी बीमारी या कमी के इलाज के बजाय परफॉर्मेंस बेहतर बनाने के मकसद से दी जाने वाली सलाह को सही नहीं ठहराया जा सकता।' गाइडेंस के मुताबिक, स्क्रीनिंग की शुरुआत लक्षणों और जोखिम वाले कारकों (रिस्क फैक्टर्स) के व्यवस्थित आकलन से होती है। अगर यह आकलन पॉजिटिव आता है या लिस्ट में शामिल कोई जोखिम कारक मौजूद होता है, तो इसके बाद ब्लड टेस्ट किया जाता है। स्क्रीनिंग की जरूरत का मतलब यह नहीं है कि हर सर्विस मेंबर को अपने-आप हार्मोन ट्रीटमेंट मिल जाएगा। बीमारी का पता लगाने के लिए लगातार कम टेस्टोस्टेरोन लेवल और उससे जुड़े लक्षणों का होना जरूरी है। सिर्फ लैब की कम रीडिंग या सिर्फ लक्षण काफी नहीं हैं। गाइडलाइन के अनुसार, अलग-अलग दिनों में खाली पेट सुबह के समय खून के दो सैंपल लेने चाहिए। इसमें यह भी कहा गया है कि अगर टोटल टेस्टोस्टेरोन रीडिंग नॉर्मल रेंज में होने के बावजूद लक्षण बने रहते हैं, तो आगे और टेस्ट किए जाने चाहिए।

इसके लक्षणों में क्या होती है : इसके लक्षणों में ऊर्जा में कमी, ध्यान लगाने में दिक्कत, मांसपेशियों का कम होना और उदास महसूस करना शामिल हो सकता है। गाइडेंस में चेतावनी दी गई है कि ये लक्षण नींद की कमी, मानसिक तनाव, जरूरत के हिसाब से कैलोरी न लेने और मिलिट्री सर्विस में आम दूसरी स्थितियों जैसे भी हो सकते हैं। गाइडेंस में बताए गए मिलिट्री सर्विलांस रिकॉर्ड से पता चलता है कि 2018 और 2025 के बीच, हर साल 1% से भी कम पुरुष सर्विस मेंबर में एक्टिव क्लिनिकल डायग्नोसिस पाया गया।

टेस्टोस्टेरोन थेरेपी से क्या फायदा होते है : डॉक्यूमेंट में कहा गया है कि टेस्टोस्टेरोन थेरेपी से शरीर की बनावट और बोन मिनरल डेंसिटी में फायदे देखे गए हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि ऊर्जा, जीवन-शक्ति, शारीरिक कार्यक्षमता या सोचने-समझने की क्षमता (कॉग्निशन) को बेहतर बनाने के लिए इसके इस्तेमाल का समर्थन करने वाले सबूत नहीं हैं। साथ में दी गई मरीजों के लिए जानकारी वाली शीट से यह साफ होता है कि इलाज करवाना एक विकल्प है।

थेरेपी से जिनकी हालत स्थिर है। उन्हें आम तौर पर बिना किसी विशेष छूट (वेवर) के तैनाती के लिए भेजा जा सकता है, बशर्ते दवा का प्रकार ऐसा हो। इलाज करने वालों को तैनाती की अवधि और उसके बाद के 90 दिनों के लिए पर्याप्त दवा का इंतजाम करना होगा, या फिर दोबारा दवा सप्लाई करने की योजना का रिकॉर्ड रखना होगा। खास तरह की ड्यूटी के लिए अलग नियम लागू रहेंगे।

35 मिलियन डॉलर के पोंजी केस में भारतीय मूल के शख्स को 11 साल की जेल

वाशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका में 35 मिलियन डॉलर से ज्यादा की पोंजी स्कीम के मामले में भारतीय मूल के निवेशक सिद्धार्थ जवाहर को 11 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। इस मामले में अमेरिकी फुटबॉल खिलाड़ी और टेलर स्विफ्ट के पति ट्रैविस केल्से का नाम भी पीड़ित निवेशकों में शामिल किया गया है। अदालत में मंगलवार को अभियोजन पक्ष ने 64 पीड़ितों के नाम पढ़े, जिनमें 38 वर्षीय ट्रैविस केल्से का नाम भी शामिल था। हालांकि, केल्से ने इस मामले में कितनी रकम निवेश की थी या उन्हें कितना नुकसान हुआ, इसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है।

कौन हैं सिद्धार्थ जवाहर : सिद्धार्थ जवाहर टेक्सास स्थित निवेश कंपनी स्विफ्टआर्क कैपिटल एलएलसी के संस्थापक थे। अभियोजन पक्ष के मुताबिक, उन्होंने निवेशकों से 35 मिलियन डॉलर से ज्यादा जुटाए और बाद में नए निवेशकों से मिली रकम का इस्तेमाल पुराने निवेशकों को भुगतान करने के लिए किया। यह पोंजी स्कीम का तरीका है।

जवाहर ने जनवरी में तीन संघीय वायर फ्रॉड आरोपों में अपना अपराध स्वीकार किया था। अदालत ने उन्हें 11 साल की संघीय जेल की सजा सुनाने के साथ 31.35 मिलियन डॉलर की भरपाई करने का आदेश दिया है।

ट्रैविस केल्से कैसे जुड़े : 2021 में फोर्ब्स में प्रकाशित एक रिपोर्ट में ट्रैविस केल्से को स्विफ्टआर्क के एक फंड के निवेशक के तौर पर बताया गया था। इस फंड की सह-स्थापना सिद्धार्थ जवाहर ने की थी। केल्से के अलावा एनबीए खिलाड़ियों टिम हार्डवे जूनियर, गैरी हैरिस और मेसन प्लमली के नाम भी उस फंड के निवेशकों में बताए गए थे। हालांकि, इन खिलाड़ियों की मौजूदा मामले में पीड़ित के तौर पर स्थिति स्पष्ट नहीं है। केल्से ने जवाहर के फंड में कितनी रकम लगाई थी इसका भी सार्वजनिक रूप से खुलासा नहीं हुआ है। अभियोजन पक्ष ने यह जानकारी भी नहीं दी कि इस मामले में केल्से की सटीक भूमिका या वित्तीय नुकसान कितना था।

निवेशकों के पैसों का क्या किया : अभियोजन पक्ष के अनुसार, जवाहर ने निवेशकों से मिली रकम का केवल करीब 10 मिलियन डॉलर निवेश किया। बाकी रकम के एक हिस्से का इस्तेमाल पुराने निवेशकों को भुगतान करने और निजी खर्चों के लिए किया गया। अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि जवाहर ने निजी विमान की उड़ानों, महंगे होटलों और महंगे रेस्तरां पर भी पैसे खर्च किए। अदालत में पेश दस्तावेजों के अनुसार, सजा सुनाए जाने से पहले समर्थन जुटाने के लिए उन्होंने अगस्त में राजनीतिक कंसल्टिंग फर्म एक्सियम स्ट्रैटेजीज को 10,000 डॉलर का भुगतान भी किया था। जवाहर भारत के रहने वाले हैं और अभियोजन पक्ष के अनुसार वह 2005 से बिना कानूनी इमिग्रेशन स्टेटस के अमेरिका में रह रहे थे।

कैमरून में बोको हराम का हमला, 13 नागरिकों की मौत, एक घायल

याउंडे, एजेंसी। कैमरून के सुदूर उत्तरी क्षेत्र में बोको हराम के आतंकियों के कथित हमले में कम से कम 13 नागरिकों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया। यह हमला गुरुवार को स्थानीय समय के अनुसार रात करीब 1 बजे से 2 बजे के बीच लोगोन-एट-चारी डिवीजन के मकरी सब-डिवीजन के माडेगौआ इलाके में हुआ। हमले के समय स्थानीय लोग अपने घरों में सो रहे थे। नाम न बताने की शर्त पर एक अधिकारी ने बताया कि हमलावर इलाके में घुस आए और 13 नागरिकों की मौके पर ही हत्या कर दी। हमले में बचा एक व्यक्ति घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों का मानना है कि यह हमला बदले की कार्रवाई हो सकता है। कुछ महीने पहले सुरक्षा बलों ने बोको हराम के आतंकियों के लिए भेजे जा रहे गोला-बारूद के एक बड़े जखीरे को जब्त किया था। इससे पहले अगस्त में कैमरून के सुदूर उत्तरी क्षेत्र में ही संदिग्ध बोको हराम आतंकियों ने कांगलेरी गांव पर हमला किया था। इस हमले में कम से कम आठ लोगों की मौत हुई थी और एक व्यक्ति घायल हुआ था।

स्थानीय सूत्रों के अनुसार, यह हमला 7 अगस्त की रात करीब 11 बजे हुआ था। हथियारबंद हमलावर अंधेरे का फायदा उठाकर गांव में घुसे थे और वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो गए थे। हमले में छह लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि तीन लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां बाद में दो लोगों की मौत हो गई। हालांकि, अधिकारियों ने अभी तक इस हमले की पूरी परिस्थितियों की पुष्टि नहीं की है। उसी रात नाइजीरिया की सीमा के पास मोकोलो जिले के टूरू शहर में भी बोको हराम से जुड़े संदिग्ध हथियारबंद लोगों की गतिविधियां सामने आई थीं।

नाइजीरिया में अवैध खनन के आरोप में पकड़े गए कम से कम 33 लोगों की हिरासत में मौत

अबुजा, एजेंसी। नाइजीरिया के नाइजर राज्य में सुरक्षा एजेंसी की कोठरी में बंद अवैध खनन के 33 संदिग्ध मृत पाए गए हैं। अधिकारियों ने किसी अज्ञात बीमारी या संक्रमण फैलने की आशंका जताई है, जबकि एक जीवित बचे व्यक्ति का आरोप है कि कोठरी में दम घुटने से यह हादसा हुआ। पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है।

नाइजीरिया में अवैध खनन के आरोप में गिरफ्तार किए गए कम से कम 33 लोग बृहस्पतिवार को मृत पाए गए। ऐसी आशंका है कि इनलोगों की मौत संक्रमण के कारण हुयी है। अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी।

नाइजीरिया के अधिकारियों ने आशंका जताई है कि अवैध खनन के आरोपियों की मौत किसी संक्रमण के फैलने के कारण हुई है। हालांकि, इसमें जीवित बचे दाउदा

शेहू ने बताया कि 65 लोगों को एक ऐसी कोठरी में ठूंसकर रखा गया था जहां हवा आने-जाने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी। उसने कहा कि हिरासत में रखे गए इन लोगों की मौत संभवतः दम घुटने से हुई।

'नाइजीरिया सिक्योरिटी एंड सिविल डिफेंस कोर' (एनएससीडीसी) के प्रवक्ता अबुबकर मुती ने बताया कि इन लोगों की मौत उत्तर-मध्य नाइजर राज्य में एनएससीडीसी की हिरासत में हुई। नाइजर में एनएससीडीसी के प्रमुख सुबेरू सियाका अनिविये ने बृहस्पतिवार को एक बयान में बताया कि सुरक्षा एजेंसी ने राज्य में अवैध खनन के संदेह में मंगलवार और बुधवार को इन लोगों को गिरफ्तार किया था और तभी से वे हिरासत में थे। अनिविये ने कहा कि एजेंसी को आशंका है कि इन लोगों की मौत कोई बीमारी फैलने से हुई।

उन्होंने साथ ही कहा कि मौत के असल कारण का पता लगाने के लिए शवों को एक स्थानीय अस्पताल भेजा गया है ताकि ''आगे की चिकित्सकीय जांच'' की जा सके। उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि किस बीमारी का संदेह है। शेहू ने कहा, ''हमें ठूंसकर रखा गया था और हवा आने-जाने की भी कोई व्यवस्था नहीं थी।

अचानक हमारा दम घुटने लगा और ताजा हवा के लिए हम छटपटाने लगे।'' शेहू ने अस्पताल में एपी से बातचीत की जहां शवों को परीक्षण के लिए भेजा गया है। उसने बताया कि कोठरी में बंद लोगों ने दरवाजा पीटकर सुरक्षा एजेंसी के गार्ड का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की। इस घटना में अपने दो बेटों को खोने वाले शफातु सुलेमान ने सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप करने की अपील की। नाइजर राज्य की पुलिस ने कहा कि उसने मामले की जांच शुरू कर दी है।

विदेश मंत्री जयशंकर और भूटान के राजा ने थिम्पू के ताशिचो द्जोंग में 'आशीर्वाद का दीया' जलाया

थिम्पू, एजेंसी। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने गुरुवार को भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक के साथ थिम्पू के प्रतिष्ठित ताशिचो जोंग में 'आशीर्वाद का दीया' जलाया। विदेश मंत्री जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 'ताशिचो जोंग में राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक की गरिमामयी उपस्थिति में 'आशीर्वाद का दीया' जलाया गया। हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 साल के समर्पित जनसेवा को सम्मान दिया, जिसने दुनियाभर में अनगिनत जिंदगियों पर प्रभाव डाला है। इस खास मौके पर प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे, भूटान के विदेश मंत्री डीएन धुंग्येल, भूटान में भारत के मित्र और भारतीय समुदाय

के लोग भी शामिल हुए।' इससे पहले दिन में विदेश मंत्री जयशंकर ने प्रधानमंत्री तोबगे के साथ अपनी बैठक के दौरान हिमालयी देश को 54 'मेड इन इंडिया' इलेक्ट्रिक वाहन सौंपे। विदेश मंत्री जयशंकर ने पीएम तोबगे को पीएम मोदी की ओर से शुभकामनाएं भी दीं और भूटान की प्रगति और समृद्धि के प्रति भारत की प्रतिबद्धता व्यक्त की।

बैठक के बाद विदेश मंत्री जयशंकर ने एक्स पर पोस्ट किया, 'आज थिम्पू में भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे से मिलकर खुशी हुई। पीएम मोदी की ओर से शुभकामनाएं दीं। हमारी दोस्ती और सहयोग के अनोखे संबंधों के लिए उनकी भावनाओं की गहराई से कद्र करता हूं। भारत भूटान की प्रगति और समृद्धि के लिए मजबूती से प्रतिबद्ध है।' वहीं, भूटान को 54 'मेड इन इंडिया' इलेक्ट्रिक वाहन सौंपते हुए विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि भारत ई-मोबिलिटी और सतत परिवहन की दिशा में भूटान की प्रगति का समर्थन कर रहा है।

स्वस्थ खान-पान, सक्रिय जीवन से हो रही लंबी आयु; 100 पार में 87.6% महिलाएं

टोक्यो , एजेंसी। जापान में 100 साल या उससे ज्यादा उम्र के लोगों की संख्या पहली बार एक लाख के पार पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, देश में अब 1,07,677 शतायु हैं। इनमें 94,298 महिलाएं यानी 87.6% और 13,379 पुरुष हैं। पिछले साल के मुकाबले इनकी संख्या 7,914 बढ़ी है। यह अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है।

जापान में 100 साल पार लोगों की संख्या बढ़ने के पीछे स्वस्थ खान-पान, बेहतर पोषण और जीवन परिस्थितियों में सुधार, सक्रिय रहना, नियमित स्वास्थ्य जांच और बेहतर स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाओं को प्रमुख वजह माना जाता है। विशेषज्ञों के मुताबिक, महिलाओं के अधिक समय तक जीवित रहने की एक वजह इस पीढ़ी के पुरुषों में धूम्रपान और शराब का अधिक चलन भी रहा। पुरुषों का ज्यादा शारीरिक मेहनत वाले कामों में रहना भी एक कारण माना जाता है। उम्र बढ़ने के बाद महिलाओं का परिवार और समुदाय से जुड़े रहना भी उनके लिए फायदेमंद रहा। उपलब्धि के साथ बड़ी चुनौती भी शतायु लोगों की बढ़ती संख्या जापान के लिए उपलब्धि के साथ चुनौती भी है। देश पहले से ही घटती आबादी और बढ़ते बुजुर्ग वर्ग से जूझ रहा है। 2020 से 2025 के बीच जापान की आबादी करीब 31 लाख कम हुई और अब देश की कुल आबादी करीब 12.23

करोड़ है। जन्मदर कम होने से युवा और कामकाजी आबादी घट रही है। इससे पेंशन, स्वास्थ्य सेवाओं और सामाजिक सुरक्षा पर दबाव बढ़ रहा है। ग्रामीण इलाकों में इसका असर ज्यादा है। इस समय जापान की कुल आबादी करीब 12.26 करोड़ है।

सबसे बुजुर्ग महिला 114 और पुरुष 112 साल के जापान की सबसे बुजुर्ग जीवित महिला फुयो किशिमोटो हैं, जो क्योटो की रहने वाली हैं। उनकी उम्र 114 वर्ष है। सबसे बुजुर्ग पुरुष हिकारू काटो हैं, जो कुमामोटो के रहने वाले हैं और 112 वर्ष के हैं। निगाता के ओसोनोगो गांव के 107 वर्षीय तेत्सुओ सातो भी शतायु लोगों में शामिल हैं। सुनने और देखने में परेशानी के बावजूद वह खुद को व्यस्त रखते हैं। 1963 में सिर्फ 153 थे जापान में शतायु लोगों की संख्या 1963 में सिर्फ 153 थी। 1981 में यह एक हजार, 1998 में 10 हजार और 2012 में 50 हजार के पार पहुंच गई। 2025 में यह 99,763 थी, जो अब एक लाख पार हो गई है।

पाकिस्तान में कंगाली का असर ! सरकारी गाड़ियों का पेट्रोल आधा; विदेश यात्रा पर भी ब्रेक

इस्लामाबाद, एजेंसी। आर्थिक दबाव से जूझ रहे पाकिस्तान ने सरकारी खर्च कम करने के लिए अब सीधे सरकारी गाड़ियों से लेकर विदेश यतक पर कैंची चला दी है. पाकिस्तान सरकार ने गुरुवार को जारी आदेश में सरकारी वाहनों के लिए ईंधन की उपलब्धता 50 फीसदी घटाने का फैसला किया है. यह व्यवस्था तीन महीने के लिए लागू रहेगी. हालांकि सेना, कानून-व्यवस्था और जरूरी सेवाओं से जुड़े ऑपरेशनल वाहनों को इससे बाहर रखा गया है.

पाकिस्तानसरकार ने नई सरकारी गाड़ियां खरीदने पर पूरी तरह रोक लगा दी है. इतना ही नहीं, IT से जुड़ी खरीद को छोड़कर दूसरे टिकाऊ सामान की खरीद पर भी रोक लगा दी गई है. यानी फिलहाल सरकारी दफ्तरों में नई गाड़ी और नया सामान खरीदने का रास्ता बंद रहेगा.

विदेश यात्रा भी इमरजेंसी मोड में : अगले तीन महीनों तक सरकारी अधिकारियों की विदेश यात्राओं पर पूरी रोक रहेगी. यहां तक कि जरूरी यात्राओं को भी सामान्य तौर पर मंजूरी नहीं होगी. कुछ सीमित अपवाद रखे गए हैं, जबकि अनिवार्य यात्राओं में मंत्रियों, सलाहकारों और अन्य सरकारी पदाधिकारियों को इकोनॉमी क्लास में सफर करना होगा. बैठकों के लिए भी सरकार ने कहा है कि जहां संभव हो, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग का इस्तेमाल

किया जाए. सरकारी खर्च पर सेमिनार, ट्रेनिंग और कॉन्फ्रेंस आयोजित करने पर भी रोक लगाई गई है.

दावतों पर भी सरकारी ब्रेक : पाकिस्तान सरकार ने सरकारी आधिकारिक डिनर की मेजबानी पर भी रोक लगा दी है. अपवाद सिर्फ विदेशी प्रतिनिधिमंडलों के लिए रखा गया है. इतना ही नहीं, शादी से जुड़े कार्यक्रमों में सिर्फ एक डिश परोसने का निर्देश दिया गया है. और बाजारों की टाइमिंग भी जस की तस रहेगी–दुकानें और बाजार रात 9 बजे, मैरिज हॉल 10 बजे और रेस्तरां-कैफे रात 11 बजे तक बंद करने होंगे. टेकअवे और होम डिलीवरी को इससे छूट दी गई है. पाकिस्तान सरकार ने साथ ही वित्त वर्ष 2026-27 के गैर-ईआरई बजट में 5 फीसदी कटौती का फैसला किया है. सरकार ने प्रांतीय और क्षेत्रीय ससरकारी वाहनों के ईंधन में 50 फीसदी कटौती कैबिनेट डिवीजन की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, सरकारी और प्रशासनिक वाहनों के लिए ईंधन आवंटन आधा कर दिया गया है। यह व्यवस्था तीन महीने तक लागू रहेगी। हालांकि सशस्त्र बलों, सिविल आर्म्ड फोर्सेज, कानून-व्यवस्था से जुड़ी एजेंसियों और जरूरी सेवाओं से जुड़े ऑपरेशनल वाहनों को इससे छूट दी गई है। सरकार ने सभी तरह के नए वाहनों की खरीद पर भी रोक लगा दी है। इसके साथ ही आईटी से जुड़ी खरीद को छोड़कर टिकाऊ सामान की सरकारी खरीद पर प्रतिबंध लगाया गया है। विकास परियोजनाओं को इन दोनों प्रतिबंधों से बाहर रखा गया है।रकारों को भी इसी तरह के उपाय अपनाने पर विचार करने को कहा है.

शादी में अब सिर्फ एक डिश : पाकिस्तान सरकार के नए निर्देशों का असर शादी और अन्य समारोहों पर भी पड़ेगा। रिपोर्ट के मुताबिक, मैरिज फंक्शन और शादी से जुड़े आयोजनों में अब केवल एक डिश परोसने की अनुमति होगी। यह कदम गैर-जरूरी खर्च और संसाधनों की खपत कम करने के उद्देश्य से उठाया गया है। इसके अलावा मैरिज हॉल और अन्य समारोह स्थल रात 10 बजे तक बंद करने होंगे। रेस्टोरेंट, कैफे और अन्य खाने-पीने के आउटलेट्स को रात 11 बजे तक बंद करने का निर्देश दिया गया है।

स्वामी,मुद्रक व् प्रकाशकः सुरेश मौर्या द्वारा अष्ठ विनायक ओफ़्सेट एफपी,149 प्लोट 26 खोडीयारनगर,सिद्धिविनायक मंदीर के पास ,भाटेना) हो.सो अंजना सुरत गुजरात से मुद्रित एवं 191 महादेव नगर उधना सुरत गुजरात से प्रकाशित संपादक : सुरेश मौया (M) 9879141480 RNI No.:GUJHIN/2018/75100 (Subject to Surat jurisdiction)

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

29 करोड़ का बना प्लेटफार्म, पहली बारिश में खुली व्यवस्था की पोल

विदिशा (एजेंसी)। 29 करोड़ रुपये की लागत से तैयार किए गए रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म पर पहली ही बारिश में निर्माण की गुणवत्ता और व्यवस्थाओं की पोल खुल गई। तेज बारिश के दौरान प्लेटफार्म पर तेज धार में पानी टपकने लगा, जिससे यात्रियों को छाता लेकर खड़ा होना पड़ा। यात्रियों का कहना है, करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद यदि बारिश से बचाव की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है. तो ऐसे निर्माण पर सवाल उठना स्वाभाविक है। कई यात्रियों को ट्रेन का इंतजार करते समय भीगने से बचने के लिए इधर-उधर खड़ा होना पड़ा। यात्रियों ने जिम्मेदार अधिकारियों से निर्माण की गुणवत्ता की जांच कराने और बारिश के पानी से बचाव की स्थायी व्यवस्था करने की मांग की है। करोड़ों की लागत के बावजूद पहली बारिश में सामने आई खामी ने निगरानी और निर्माण एजेंसी की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

साइबर क्राइम पोर्टल पर 54 लाख आईं शिकायतें, सिर्फ 1.30 लाख में एफआईआर दर्ज

नई दिल्ली (एजेंसी)। देश में साइबर क्राइम के मामलों में एफआईआर दर्ज होने की दर बेहद कम है। 2019 से 2024 के बीच छह साल में नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर 53.93 लाख शिकायतें आईं, लेकिन एफआईआर सिर्फ 1.30 लाख मामलों में ही दर्ज की गईं। राज्यसभा की गृह मामलों से संबंधित स्थायी समिति की रिपोर्ट में ये जानकारी सामने आई। 31 सदस्यीय समिति के अध्यक्ष डॉ. राधामोहन दास अग्रवाल हैं। इस पर चिंता जताते हुए समिति ने अपराध के आंकड़ों और कानून-व्यवस्था के दावों पर सवाल उठाए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि साइबर हेल्पलाइन 1930 और वेबसाइट पर शिकायत के बाद भी फॉलो-अप में देरी होती है। रिपोर्ट के मुताबिक क्राइम रेट कम दिखाने के लिए पुलिस एफआईआर के बजाय सिर्फ गैर-संज्ञेय रिपोर्ट देती है, जिससे गंभीर अपराध छिप जाते हैं और लोग न्याय से वंचित होते हैं। राज्यों द्वारा एनसीआरबी को डेटा भेजने में 1.5 से 2 साल की देरी होती है, जिससे सुरक्षा नीतियां और बजट पुराने आंकड़ों पर बनते हैं। अपराधों की संख्या दबने से असुरक्षित इलाकों में नए थाने, सीसीटीवी और जरूरी पुलिस बल नहीं मिल पाते। समिति ने बताया कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो प्रिंसिपल ऑफेंस रूल पर काम करता है यानी अगर किसी महिला का अपहरण करके उसके साथ लूटपाट की और फिर वीडियो ऑनलाइन लीक कर दिया गया। एनसीआरबी इसे सिर्फ अपहरण में दर्ज करेगा। साइबर अपराध, महिला उत्पीड़न और लूट का सेकेंडरी डेटा छोड़ दिया जाएगा। इस तरह लाखों सेकेंडरी अपराध डेटा से पूरी तरह गायब हो जाते हैं।

आगर मालवा में भीषण हादसा : उफनते नाले में बही कार, 8 श्रद्धालुओं की मौत

आगर मालवा (एजेंसी)। मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले में भयावह सड़क हादसा सामने आया है, जहां श्रद्धालुओं से भरी कार बारिश से उफनते नाले में बह गई। इस दर्दनाक घटना में तीन बच्चों सहित कुल आठ लोगों की जान चली गई। यह हादसा नलखेड़ा स्थित प्रसिद्ध मां बगलामुखी मंदिर के समीप हुआ। मिली जानकारी के अनुसार, मृतक श्रद्धालु मां बगलामुखी के दर्शन करने नलखेड़ा पहुंचे थे। शुक्रवार देर रात या शनिवार सुबह, जब कार चालक ने मंदिर के समीप बरसाती नाले को पार करने का प्रयास किया, तब वहां पानी के तेज बहाव का सही अंदाजा नहीं लग सका। नतीजतन, कार अनियंत्रित होकर नाले के भीषण बहाव में बह गई। शनिवार की सुबह जब नाले का पानी कुछ उतरा, तब राहगीरों की नजर बही हुई कार पर पड़ी। उन्होंने तत्काल पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद राहत और बचाव कार्य शुरू किया। कार के भीतर से सभी आठ शवों को बाहर निकाला गया। आगर मालवा पुलिस ने घटना में आठ मौतों की पुष्टि की है। मरने वालों में तीन बच्चे, दो महिलाएं और तीन पुरुष शामिल हैं। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि कार में सवार सात लोग ओडिशा के निवासी थे, जिन्होंने उज्जैन से कार किराए पर ली थी और वे मां बगलामुखी के दर्शनों के लिए जा रहे थे। इस हृदयविदारक हादसे के बाद मौके पर भारी संख्या में लोग जुट गए और अफरा-तफरी का माहौल बन गया। पुलिस आगे की जांच कर रही है।

मनी लॉन्ड्रिंग केस : सीएम सोरेन पीएमएलए कोर्ट में नहीं हुए पेश

रांची(एजेंसी)। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची की विशेष पीएमएलए अदालत में बड़गाईं की 8.86 एकड़ जमीन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में व्यक्तिगत रूप से पेश नहीं हुए। उनके अधिवक्ता ने अदालत में को बताया कि मुख्यमंत्री पूर्वनिर्धारित संवैधानिक दायित्वों में व्यस्त हैं। इसके बाद अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 21 सितंबर की तारीख तय कर उन्हें शाम चार बजे व्यक्तिगत या वर्चुअल माध्यम से पेश होने का निर्देश दिया है। यह घटनाक्रम झारखंड हाईकोर्ट द्वारा उनकी डिस्चार्ज याचिका खारिज होने के बाद सामने आया। हाईकोर्ट ने रांची की विशेष पीएमएलए अदालत के उस आदेश को बरकरार रखा था, जिसमें सोरेन की डिस्चार्ज याचिका को अस्वीकार किया गया था, जिससे निचली अदालत में आगे की कार्यवाही का रास्ता साफ हुआ था।

नाबालिग से दुष्कर्म : प्रियंका बोलीं- जिम्मेदारी लेने से बच रही सरकार

नई दिल्ली, एजेंसी।

दिल्ली में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म और निर्मम हत्या के बाद कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने देश में महिला सुरक्षा की स्थिति पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि महिला सुरक्षा के लिए कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट में इस क्रूर घटना का जिक्र करते हुए कहा कि एक 17 साल की बच्ची के साथ क्रूरता की सारी हदें पार कर दी गईं और उसे बर्बरता से मार डाला गया। उन्होंने याद दिलाया कि कुछ ही दिन पहले एक और नाबालिग लड़की का बलात्कार किया गया था।

प्रियंका गांधी ने महिला सुरक्षा के नाम पर सिर्फ खोखली बातें होने का आरोप लगाते हुए कहा कि सैकड़ों महिलाओं पर अत्याचार और हिंसा होती है, लेकिन अपराधी ठोस कार्रवाई की उम्मीद नहीं कर सकते, यहां तक कि एफआईआर भी दर्ज नहीं होती। उन्होंने समाज और सरकार दोनों को महिलाओं को सुरक्षा, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार देने में पूरी तरह विफल करार दिया। इससे पहले, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी दिल्ली की घटना पर चिंता व्यक्त की थी। उन्होंने कहा था कि महिलाओं की सुरक्षा के बिना भारत आगे नहीं बढ़ सकता। राहुल गांधी ने अपनी पोस्ट में लिखा, दिल्ली में 17 साल की युवती के साथ गैंगरेप हुआ, उसकी हत्या कर शव खुले मैदान में फेंक दिया गया। राजधानी में इतनी बड़ी दरिंदगी और पुलिस को कई दिनों तक भनक नहीं लगती। दुर्भाग्य है कि दिल्ली आज राजधानी नहीं, महिलाओं के लिए हर दिन की खौफनाक कहानी बनकर रह गई है। उन्होंने गृह मंत्री से दिल्ली पुलिस के अधीन होने का सवाल उठाते हुए पूछा कि महिला सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिर किसकी है, क्योंकि अपराधी तो बेखौफ घूम रहे हैं। उन्होंने दरिंदों की तत्काल गिरफ्तारी, कड़ी कार्रवाई और सजा की मांग की, साथ ही इस आपराधिक गैर-जिम्मेदारी की जवाबदेही तय करने को कहा। यह मामला 13 सितंबर को सामने आया था, जब उत्तरी दिल्ली के स्वरूप नगर इलाके में एक बुरी तरह सड़ी-गली लाश मिली। जांच में पीड़िता की पहचान हुई और पता चला कि इस वारदात को चार लोगों ने अंजाम दिया, जिनमें तीन नाबालिग हैं। आरोपियों ने बाद में लड़की के शव को खुले इलाके में फेंक दिया था। पुलिस के अनुसार, पीड़िता आरोपियों को जानती थी और उनके साथ टेंपो में सफर कर रही थी। सफर के दौरान सभी ने शराब पी और फिर लड़की के साथ दुष्कर्म कर चाकू से गोदकर उसकी हत्या कर दी।

आईआईटी बॉम्बे के छात्र की मौत पर छात्रों ने किया प्रदर्शन

नई दिल्ली (एजेंसी)। आईआईटी बॉम्बे में एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग विभाग के छात्र ने हॉस्टल के कमरे में आत्महत्या कर ली। घटना के बाद से ही कैंपस में तनाव है और गुस्साए छात्रों ने देर रात विरोध-प्रदर्शन किया। संस्थान ने बताया कि शुक्रवार को ही अधिकारियों ने उसे परीक्षा के दौरान मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हुए पकड़ा था। छात्र ने सवाल का जवाब पाने के लिए परीक्षा का प्रश्न पत्र चैटजीपीटी पर अपलोड किया था।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आईआईटी बॉम्बे प्रशासन ने एक बयान जारी कर स्पष्ट किया है कि छात्र के खिलाफ कोई दंडात्मक या अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू नहीं की गई थी। पकड़े जाने के बाद विभागाध्यक्ष और कोर्स इंस्ट्रक्टर ने छात्र से बात की थी। संस्थान के मुताबिक अधिकारियों ने छात्र की काउंसलिंग की और उसे भरोसा दिलाया कि इस घटना का उसके एकेडमिक करियर पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। बाद में वह अपने हॉस्टल के कमरे में लौट गया। इसके बाद शुक्रवार शाम अधिकारियों को वह कमरे में मृत मिला। संस्थान ने छात्र के बारे में और जानकारी नहीं दी।

संस्थान ने कहा कि उसने छात्र के दोस्तों, क्लासमेट्स, फैकल्टी सदस्यों और घटना से प्रभावित अन्य लोगों को मदद दी है। संस्थान ने कहा कि मौत से जुड़ी परिस्थितियों की जांच संबंधित अधिकारियों द्वारा की जा रही है। छात्र की मौत की खबर फैलते ही कैंपस में हलचल मच गई। बड़ी संख्या में छात्रों ने एकत्र होकर देर रात विरोध-प्रदर्शन किया। यह घटना ऐसे समय में सामने आई है जब अभी हाल ही में आईआईटी दिल्ली में एमएससी फिजिक्स के एक छात्र ने आत्महत्या कर ली थी।

तमिलनाडु में स्कूली बच्चों को खाने में मिलेगी चिकन बिरयानी

-सीएम विजय 22 को पेरुंथलैवर कामराजर ब्रेकफ़ास्ट स्कीम के विस्तार की करेंगे शुरुआत

चेन्नई, एजेंसी।

तमिलनाडु के सीएम सी जोसेफ विजय 22 सितंबर को छठी से आठवीं कक्षा के छात्रों के लिए पेरुंथलैवर कामराजर ब्रेकफ़ास्ट स्कीम के विस्तार की शुरुआत करेंगे। स्कूल शिक्षा मंत्री ए राजमोहन ने बताया कि सीएम विजय ने सामान्य खाने के अलावा अलग-अलग तरह के और स्वादिष्ट मेन्यू विकल्प लाने के लिए एक विशेष समिति बनाने का आदेश दिया है। उन्होंने मेन्यू में नए बदलावों का संकेत देते हुए चिकन बिरयानी जैसे नॉन-वेज विकल्प शामिल करने की बात भी कही है।

इस विस्तारित योजना से 15,454 सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में छठी से आठवीं कक्षा में पढ़ने वाले करीब 15.30 लाख अतिरिक्त छात्रों को लाभ मिलेगा। यह छात्रों के पोषण के लिए एक अहम कदम है, जिससे यह तय होगा कि वे अपने दिन की शुरुआत सेहतमंद तरीके से करें। इस विस्तार के लिए चालू वित्त वर्ष में 217.63 करोड़ रुपए का अतिरिक्त फंड आवंटित किया गया है, जिससे इस कार्यक्रम का कुल बजट बढ़कर 724 करोड़ रुपए हो गया है। 22 सितंबर को विस्तारित योजना शुरू करने का फैसला यहां सचिवालय में विजय की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक के दौरान लिया गया।

उम्मीद है कि सीएम यहां तिरुवनमियूर के एक सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल में इस पहल की शुरुआत करेंगे। इस योजना को 17 सितंबर को शुरू होना था, लेकिन सीएम विजय की लंदन यात्रा के कारण इसे टाल दिया गया था। इसे चेंगलपट्टू और तिरुप्पुर जिलों में लागू नहीं किया जाएगा, क्योंकि वहां क्रमशः मदुरंतकम और धारापुरम विधानसभा क्षेत्रों में 6 अक्टूबर को होने वाले उपचुनावों के लिए चुनाव आयोग की आदर्श आचार संहिता लागू है। मेन्यू में उपमा, खिचड़ी और पोंगल जैसे पौष्टिक मुख्य व्यंजन शामिल हैं, साथ ही हफ्ते में दो बार मोटे अनाज से बने विकल्प भी दिए जाएंगे।

तिरुपति लड्डू घी में मिलावट: ईडी ने प्रमोटर को दबोचा

तिरुपति, एजेंसी।

तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसिद्ध लड्डू प्रसाद में इस्तेमाल होने वाले घी को लेकर एक बार फिर विवाद गहरा गया है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दावा किया है कि वर्ष 2019 से 2024 के बीच तिरुमला तिरुपति देवस्थानम (टीटीडी) को जिस घी की आपूर्ति की गई, उसमें कथित तौर पर शुद्ध गाय के घी के बजाय रिफाइंड पाम ऑयल, पाम कर्नेल ऑयल और पामोलीन जैसे वनस्पति तेलों का इस्तेमाल किया गया। एजेंसी के अनुसार, इन पदार्थों को घी जैसा रूप और गुण देने के लिए कुछ रसायनों का भी इस्तेमाल किए जाने का आरोप है। ईडी ने इस अवधि में करीब 230 करोड़ रुपये की कथित संदिग्ध आपूर्ति की बात कही है।

मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने सुकृति फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रवर्तक कैलाश चंद मंगला को गिरफ्तार किया है। एजेंसी का आरोप है कि उनकी कंपनी से करीब 96 करोड़ रुपये मूल्य का कथित मिलावटी घी तैयार कर आपूर्ति किया गया। जांच के दौरान एजेंसी ने एमजी-90, मोनोग्लिसराइड्स, मायवेसिट सॉफ्ट 400 और एसीटिक एसिड एस्टर जैसे रसायनों के इस्तेमाल का भी दावा किया है। आरोप है कि वनस्पति तेलों में इन पदार्थों को मिलाकर ऐसा मिश्रण तैयार किया गया, जिसे घी के रूप में आपूर्ति किया जा सके। तिरुपति मंदिर में लड्डू प्रसाद का धार्मिक और भावनात्मक महत्व बेहद व्यापक है। देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालु इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं और अपने साथ भी ले जाते हैं। ऐसे में प्रसाद में इस्तेमाल होने वाली सामग्री की गुणवत्ता को लेकर सामने आया कोई भी सवाल श्रद्धालुओं की आस्था के साथ-साथ खाद्य गुणवत्ता और आपूर्ति व्यवस्था पर भी असर डालता है। प्रवर्तन निदेशालय अब यह पता लगाने में जुटा है कि कथित मिलावटी घी का उत्पादन किस स्तर पर हुआ, इसकी आपूर्ति किस माध्यम से की गई और पूरी प्रक्रिया में कौन-कौन लोग शामिल थे। जांच का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि इतनी बड़ी मात्रा में कथित रूप से मिलावटी उत्पाद की आपूर्ति के दौरान गुणवत्ता जांच की प्रक्रिया में इसे पकड़ा क्यों नहीं गया। कैलाश चंद मंगला की गिरफ्तारी के बाद मामले में जांच तेज होने की संभावना है। एजेंसी कंपनी से जुड़े दस्तावेजों, उत्पादन प्रक्रिया, खरीद और आपूर्ति से संबंधित रिकॉर्ड तथा भुगतान के विवरण की पड़ताल कर रही है। हालांकि, प्रवर्तन निदेशालय द्वारा लगाए गए ये आरोप जांच का हिस्सा हैं और अदालत में इनकी अंतिम पुष्टि होना अभी बाकी है। मामले में दोष और जिम्मेदारी का निर्धारण उपलब्ध साक्ष्यों तथा न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर ही होगा।

मायने-12 केस, 3 हत्या फिर भी कांग्रेस नंदीग्राम से बनाया उम्मीदवार

लखनऊ, एजेंसी।

कोलकाता(ईएमएस)। पश्चिम बंगाल की प्रतिष्ठित नंदीग्राम विधानसभा सीट पर उपचुनाव से ठीक पहले, कांग्रेस प्रत्याशी मिलन प्रधान की गिरफ्तारी ने राज्य की राजनीति में भूचाल ला दिया है। कांग्रेस के शीर्ष नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस कार्रवाई को लोकतंत्र की हत्या और राजनीतिक बदले की भावना करार दिया, वहीं मिलन प्रधान के चुनावी हलफनामे में तीन-तीन हत्या के गंभीर मामलों के खुलासे ने कांग्रेस को बचाव की मुद्रा में खड़ा कर दिया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी गिरफ्तारी को अत्याचारी कूटनीति बताते हुए कांग्रेस प्रत्याशी को अपना समर्थन दिया था।

राहुल गांधी और कांग्रेस के अन्य वरिष्ठ नेताओं द्वारा गिरफ्तारी को केंद्र और राज्य सरकार की मिलीभगत बताए जाने के तुरंत बाद, मिलन प्रधान का चुनावी हलफनामा सार्वजनिक हुआ। इस हलफनामे में कांग्रेस उम्मीदवार ने स्वयं स्वीकार किया है कि उनके खिलाफ तीन अलग-अलग हत्या के मामले दर्ज हैं। इन तीनों मर्डर केस में अदालतों की ओर से लंबे समय से

गिरफ्तारी वारंट लंबित थे। नंदीग्राम पुलिस स्टेशन में दर्ज मामलों के अतिरिक्त, खेजुरी थाने में भी आर्म्स एक्ट और अन्य संगीन धाराओं के तहत वारंट जारी किए गए थे। चुनावी विश्लेषकों और विरोधी दलों के नेताओं ने सवाल उठाया है कि जब कांग्रेस आलाकमान को अपने उम्मीदवार के खिलाफ कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट लंबित होने की जानकारी थी, तो ऐसे दागी व्यक्ति को टिकट क्यों दिया गया? कानून के प्रावधानों के अनुसार, चुनाव के दौरान किसी भी भगोड़े या गैर-जमानती वारंट वाले व्यक्ति को पुलिस किसी भी समय गिरफ्तार कर सकती है। यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या कांग्रेस ने जानबूझकर ऐसा उम्मीदवार उतारा ताकि गिरफ्तारी होने पर चुनावी माहौल में विक्टिम कार्ड खेलकर लोकतंत्र की हत्या जैसा नैरेटिव स्थापित किया जा सके। रोचक बात यह है कि ममता बनर्जी की पार्टी की उम्मीदवार संचिता प्रधान दे द्वारा नाम वापस लेने के बाद, ममता ने तुरंत कांग्रेस प्रत्याशी मिलन प्रधान को समर्थन देने का ऐलान किया था, और इसके कुछ ही घंटों के भीतर पुलिस ने कार्रवाई कर दी। राहुल गांधी के सोशल मीडिया पर राजनीतिक बदले के आरोपों के बाद, डेमोक्रेटिक तृणमूल कांग्रेस (एक विरोधी गुट) के नेता ऋतब्रत बनर्जी ने तीखी प्रतिक्रिया दी। ऋतब्रत बनर्जी ने एक पोस्ट में लिखा, नंदीग्राम से कांग्रेस प्रत्याशी मिलन प्रधान के खिलाफ हत्या के तीन मामलों में गिरफ्तारी वारंट लंबित थे। हमने खुद इसकी शिकायत दर्ज कराई थी। चुनाव के दौरान वारंट तामील कराना कानून का स्थापित नियम है। प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व ने शायद राहुल गांधी को पूरे और सही तथ्य नहीं बताए, जिसके कारण वे ऐसे आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति का बचाव कर रहे हैं।

निठारी कांड : सुरेंद्र कोली की मौत पर उठे सवाल, राज दफन होने का डर

नई दिल्ली , एजेंसी।

नोएडा के निठारी गांव ने दो दशक पहले अपने बच्चों के गायब होने का जो भयावह दर्द झेला था, शुक्रवार को सुरेंद्र कोली की मौत ने उस दर्द को फिर से ताजा कर दिया है। निठारी कांड के मुख्य आरोपियों में से एक सुरेंद्र कोली की कथित आत्महत्या पर गहरा संदेह व्यक्त किया जा रहा है। अपनी बेटी ज्योति को खो चुके सुनीता और झब्बू लाल जैसे परिजनों ने कोली की मौत की गहन जांच की मांग की है, क्योंकि उनका मानना है कि इसमें कोई गहरी साजिश हो सकती है।

झब्बू लाल और सुनीता की बेटी ज्योति भी उन बच्चों में शामिल थी, जो वर्ष 2005-06 के दौरान रहस्यमय तरीके से लापता हुई थीं। कोली की मौत की खबर सुनते ही सुनीता ने कहा, कोली ने आत्महत्या नहीं की, उसे मारा गया है। अगर उसे आत्महत्या करनी होती तो वह जेल में ही कर लेता। उसकी मौत के पीछे कोई साजिश हो सकती है। झब्बू लाल ने भी आशंका व्यक्त की कि कोली के पास निठारी कांड से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज हो सकते थे और वह भविष्य में कोई बड़ा खुलासा कर सकता था। उन्होंने निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा कि जब तक मोनिंदर सिंह पंढेर को फांसी नहीं मिलती, उन्हें न्याय नहीं मिलेगा। निठारी निवासी ग्रामीणों ने बताया कि दिसंबर 2006 में नाले में एक मासूम का पंजा मिलने के बाद ही घटनाओं की कड़ियां जुड़ने लगीं और सेक्टर-31 स्थित डी-5 कोठी जांच एजेंसियों के निशाने पर आ गई थी। इस घटना के बाद से डी-5 कोठी को लेकर ग्रामीणों के मन में आज भी एक गहरा डर समाया हुआ है। ज्योति के गायब होने के बाद, निठारी में एक के बाद एक बच्चों और युवतियों के गायब होने की घटनाएं सामने आती गईं। दिसंबर 2006 में डी-5 कोठी के आसपास नाले से मानव अवशेष मिलने के बाद यह पूरा मामला देशभर में सुर्खियों में आया। जांच में मोनिंदर सिंह पंढेर और उसके घरेलू सहायक सुरेंद्र कोली के नाम सामने आए थे। अक्टूबर 2023 में इलाहाबाद हाई कोर्ट से कई मामलों में राहत मिलने के दौरान कोली की पत्नी शांति देवी ने डासना जेल में उससे मुलाकात की थी, जहाँ कोली ने बेगुनाही की लड़ाई लड़ने की बात कही थी।

सिंधु संधि पर भारत का फैसला पाक प्रायोजित आतंकवाद के जवाब में जायज कदम

-यूएन मानवाधिकार परिषद में अंतरराष्ट्रीय वक्ताओं ने संधि निलंबित को सही ठहराया

नई दिल्ली,, एजेंसी।

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 63वें सत्र में आयोजित कॉन्फ्रेंस में अंतरराष्ट्रीय वक्ताओं ने दिल्ली के सिंधु जल संधि को निलंबित करने को सही ठहराया। गुरुवार को इस कॉन्फ्रेंस में वक्ताओं ने कहा कि भारत का यह फैसला दशकों से पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद और उसकी बदनीयती के जवाब में जायज कदम था। यह पाकिस्तान के लिए एक झटका है क्योंकि उसकी कोशिश इस मुद्दे पर दुनिया का ध्यान खींचने की है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सिंधु जल संधि पर भारत और पाकिस्तान के बीच 19 सितंबर 1960 को सिंधु प्रणाली की नदियों के पानी के इस्तेमाल को लेकर हस्ताक्षर किए गए थे। बीते साल पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत ने इस संधि को निलंबित कर दिया था। भारत ने इस कदम के पीछे का मकसद पाकिस्तान के आतंक को समर्थन देना बताया है। सामुदायिक जल अधिकार और सिंधु जल संधि को स्थगित रखने की जरूरत विषय पर आयोजित कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए ब्रुसेल्स स्थित साउथ एशिया डेमोक्रेटिक फोरम के रिसर्च डायरेक्टर सीगफ्राइड वुल्फ ने कहा कि भारत को 1960 की संधि की समीक्षा की मांग करने का पूरा अधिकार है। ये जायज है क्योंकि पाकिस्तान के व्यवहार ने संधि की प्रस्तावना में बताए गए समझौते के मकसद, उद्देश्य और भावना को कमजोर किया है।

वुल्फ ने इस संधि को भारत की तरफ से दी गई एक स्वैच्छिक रियायत बताया जो एक संरचनात्मक असंतुलन पर आधारित थी। उन्होंने पाकिस्तान के उस दावे को इंजीनियरिंग मिथक करार दिया, जिसमें उसने कहा है कि भारत नदियों के बहाव को रोक रहा है। उन्होंने बताया कि पश्चिमी नदियों पर बनी भारतीय परियोजनाएं पानी की खपत नहीं करतीं और पानी को आगे भेजने से पहले बिजली पैदा करती हैं। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद का अभियान भारत के विकास में देरी करने, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसे बदनाम करने और पानी के उस संकट से ध्यान भटकाने की एक बड़ी कोशिश का हिस्सा है, जो पूरी तरह से खुद पैदा किया गया है। इसकी जड़ें पंजाब के दबदबे, सामंती जमींदारी व्यवस्था, शहरी झुकाव और नहरों के खस्ताहाल बुनियादी ढांचे में हैं।

लंदन में रहने वाले मानवाधिकार कार्यकर्ता आरिफ आजकिया ने कहा कि पानी का अधिकार एक बुनियादी मानवाधिकार है। इससे पाकिस्तान के सैन्य तंत्र ने सिंध को वंचित रखा है। सिंध में कोट्री के पास सिंधु नदी का बहाव ऊपर की ओर नहरों के जरिए पानी मोड़े जाने के कारण बहुत कम हो गया है। भारत में हुए बड़े आतंकी हमलों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि भारत का 65 साल पुराने समझौते को निलंबित करने का फैसला सही था। एक भारतीय एनजीओ ने तर्क दिया कि इस क्षेत्र में पानी की सुरक्षा से जुड़ी बदलती स्थितियों को देखते हुए 1960

में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए समझौते का आज के मानवाधिकारों के नजरिए से फिर से मूल्यांकन किया जाना चाहिए।

एनजीओ ने कहा कि सिंधु संधि लंबे समय से चले आ रहे अंतरराष्ट्रीय सहयोग का एक अहम उदाहरण होने के बावजूद छह दशक में पानी की सुरक्षा से जुड़े हालात बदल गए हैं। इसमें आबादी में बढ़ोतरी, जलवायु परिवर्तन, ग्लेशियरों के पीछे हटने, भूजल के कम होने और नदियों के बहाव में लगातार अनिश्चितता जैसे कारण हैं।